



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 2018/कार्तिक 7, 1940

No. 349]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 2018/KARTIKA 7, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

(अधिसूचना)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2018

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. ओ.आई. 25/2017

विषय: चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए जिओलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड) के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच ।

फा.सं.06/14/2017-डीजीएडी.— समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) तथा समय समय पर उसके यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात् नियमावली के रूप में भी संदर्भित) के संबंध में; निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात् प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) ने दिनांक 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचना संख्या 06/14/2017-डीजीएडी के द्वारा चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए जिओलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड) के आयातों के विरुद्ध पाटन रोधी जांच शुरू की थी ।

1. और जबकि मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स केमिकल्स इंडिया (इसके पश्चात् 'याचिकाकर्ता' अथवा 'आवेदक' के रूप में भी संदर्भित) ने चीन के जनवादी गणराज्य (इसके पश्चात् संबद्ध देश के रूप में भी संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए जिओलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड) (इसके पश्चात् संबद्ध वस्तुओं के रूप में भी संदर्भित) के आयातों

के संबंध में पाटनरोधी जांच आरम्भ करने के लिए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात प्राधिकारी के रूप में भी संदर्भित) के समझ वर्तमान मामले में एक आवेदन प्रस्तुत किया और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया ।

2. और जबकि प्राधिकारी ने पाटन रोधी जांच आरंभ करने के लिए औचित्य ठहराने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचना संख्या 6/14/2017 -डीजीएडी के द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के होने, उसकी मात्रा और प्रभाव की जांच एवं निर्धारण करने तथा पाटन रोधी शुल्क की राशि जिसे अगर लगाया जाये, तो वह घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी की सिफारिश करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया ।

क प्रक्रिया

3. यहां नीचे दी गई निर्धारित प्रक्रिया का पालन प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच को आरंभ करने संबंधी अधिसूचना जारी करते हुए सार्वजनिक नोटिस के जारी किए जाने के बाद इस जांच के संबंध में पालन किया गया है:

- i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार इन जांचों को शुरू करने के लिए कार्रवाई करने के पूर्व पाटन रोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ii. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गए पते के अनुसार भारत में संबद्ध देश के संबंधित दूतावास; संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों; अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को जांच प्रारंभन संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने विचार जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अवगत कराएं।
- iii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास को और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध करायी।
- iv. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह यह अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी उन्हें संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ साथ भेजी गई थी।
- v. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली और पूरक प्रश्नावली भेजी:
 - क. मैसर्स चालको क्विंगडाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग ।
 - ख. मैसर्स चालको जिबो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी ।
 - ग. मैसर्स जियामेन झोंगझाओ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि. ।
 - घ. मैसर्स तियानजिन गर्कविन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि.
 - ड. मैसर्स गुवांगझाओ केमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि. ।
 - च. मैसर्स हुईइंग केमिकल इंडस्ट्री
- vi. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया और प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया :
 - क. मैसर्स इनर मंगोलिया रिसिंग रिसाइकलिंग रिसोर्स कंपनी लि.।
 - ख. मैसर्स तियानजिन गर्कविन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि.
 - ग. मैसर्स चालको सानडोंग एडवांस्ड मटीरियल कंपनी लि.।
 - घ. मैसर्स चालको क्विंगडाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि.
 - ड. मैसर्स चालको जिबो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि.
- vii. चालको सानडोंग एडवांस्ड मटीरियल कंपनी लि, चालको क्विंगडाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि., चालको जिबो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि., तियानजिन गर्कविन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि., जियामेन झोंगझाओ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि. और चाइना चैम्बर ऑफ कामर्स ऑफ मैटल, मिनरल्स एंड कैमिकल्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स द्वारा कानूनी अनुरोध भी दायर किए गए थे।

- viii. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता संघों को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी:
- क. मैसर्स निरमेश इंटरप्राइजेज प्रा.लि.
 - ख. मैसर्स पी सी कोस्मा शोप लि.
 - ग. मैसर्स जिओलाइट्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा.लि.
 - घ. मैसर्स अंकुश इंटरप्राइजेज
 - ङ. मैसर्स शंकर एक्जिम प्रा.लि.
 - च. मैसर्स बिमल एजेन्सी
 - छ. मैसर्स वघानी इंक
 - ज. मैसर्स एस बी इंटरनेशनल
 - झ. मैसर्स श्री शोप्स एंड कैमिकल इंडस्ट्रीज
 - ञ. मैसर्स प्लाज्मा एक्जिम एल एल पी
 - ट. मैसर्स निरमा लि.
 - ठ. मैसर्स देवांशी एक्सपोर्ट प्रा.लि.
 - ड. मैसर्स ओएसिस कैपिटल प्रा.लि.
 - ढ. मैसर्स देव ओवरसीज
 - ण. मैसर्स आर एस पी एल लि. (घड़ी डिटर्जेंट)
 - त. मैसर्स प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रोडक्ट्स प्रा.लि.
 - थ. मैसर्स बालेश्वर एक्जिम प्रा.लि.
 - द. मैसर्स अग्रवाल मिनरल्स
 - ध. मैसर्स आदित्या फाइनकेम प्रा.लि.
- ix. संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब दिया:
- क. मैसर्स आदित्या फाइनकेम (प्रा.)लि.
 - ख. मैसर्स हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि.
- x. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया।
- xi. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) को पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेनदेन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था जो अधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने लेनदेन की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण तथा आयातों की मात्रा की गणना के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xii. सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर आधारित भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण अथवा बिक्री करने के लिए लागत और उत्पादन की आदर्शतम लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एन आई पी) तय किया गया है जिससे कि इस तथ्य का पता लग सके कि पाटन मर्जिन की तुलना में कम पाटन रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiii. प्राधिकारी ने 25 मई, 2018 को नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया। सभी पक्षकारों जिन्होंने सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, से यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों को यह भी अनुरोध किया गया था कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोधों को प्राप्त करें और उस पर अपने उत्तर प्रस्तुत करें।
- xiv. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक समझा गया। आवश्यक संशोधन के साथ केवल इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर जहां भी लागू माना गया, विश्वास किया गया है।

- xv. याचिकाकर्ताओं ने याचिका में जांच की अवधि के रूप में अप्रैल, 2016-मार्च, 2017 (12 महीने) की अवधि का प्रस्ताव किया था। प्राधिकारी को अपेक्षाकृत अधिक अद्यतित आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित विश्लेषण करने में सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकारी ने अप्रैल, 2016 से जून, 2017 (15 महीने) के रूप में जांच की अवधि का निर्धारण किया है। क्षति के विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2013-मार्च, 2014, अप्रैल, 2014-मार्च, 2015, अप्रैल, 2015-मार्च, 2016 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल की गई।
- xvi. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का समाधान जहां भी संगत पाया गया प्राधिकारी द्वारा इस अधिसूचना में किया गया है।
- xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया गया है और इस प्रकार की सूचना पर विचार गोपनीय के रूप में और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न किए गए के रूप में विचार किया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।
- xviii. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया गया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को गैर सहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचारों/टिप्पणियों को दर्ज किया है।
- xix. इस दस्तावेज में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी के द्वारा उस पर विचार किए गए का द्योतक है।
- xx. जांच की अवधि के लिए विनिमय दर प्राधिकारी द्वारा **67.45 रु. = 1 अमरीकी डॉलर** के रूप में लिया गया है।

ख. **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

ख.1 **घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

4. घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण नीचे दिया गया है:

- विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) 'जियोलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड)' है जिसे 'सिन्थेटिक जियोलाइट 4ए' के रूप में भी जाना जाता है। जियोलाइट सुपरिभाषित संरचनाओं के साथ सूक्ष्म छेद वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सामान्य तौर पर उसमें उनके ढांचा और कैटियन में सिलिकॉन, अल्युमीनियम और ऑक्सीजन होता है, उनके छेदों के भीतर पानी और / अथवा अन्य मॉलिक्यूल होता है। कई प्राकृतिक रूप से खनिज पदार्थ के रूप में होते हैं और उनका विस्तार से खनन विश्व के कई भागों में किया जाता है। अन्य सिन्थेटिक होते हैं और उनका विभिन्न उद्योगों में विशिष्ट उपयोगों के लिए वाणिज्यिक रूप से निर्माण किया जाता है। जियोलाइट का सामान्य सूत्र एन ए एक्स [(एलओ2) x (एसआईओ2) वाई].जेड एच 2 ओ के रूप में दिया गया है।
- गोल कोने और किनारे के साथ क्यूबिकल आकार के कारण, जियोलाइट 4ए क्रिस्टल फैब्रिक्स पर नहीं रहते हैं और उन्हें धुलाई करने पर आसानी से हटाया जा सकता है। उनमें अत्यधिक तापक्रम पर भी बहुत अधिक संकुचन शक्ति होती है और 12 से कम पीएच के साथ अलकली प्रतिक्रिया भी इनमें होता है। कण का औसत आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। यह इसे कपड़े के जाल आकार से होकर गुजरने के लिए तथा उसके द्वारा ग्रे होने से रोकने के लिए उपयुक्त बनाता है। संबद्ध वस्तु का मुख्य रूप से उपयोग डिटर्जेंट में बिल्डर के रूप में होता है।
- डिटर्जेंट ग्रेड के जियोलाइट प्राथमिक रूप से जल को मृदु कोमल बनाने के लिए मिश्रण है जिसका उपयोग खारे पानी से कैल्शियम और मैगनीशियम आयरन को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके फलस्वरूप जल मृदु हो जाता है जिसके लिए वही सफाई के प्रयास के लिए कम साबुन की आवश्यकता होती है क्योंकि कैल्शियम इयन को हटाने के लिए साबुन बर्बाद नहीं होता।
- विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत आता है। संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण याचिका दायर करने के समय सीमा शुल्क उप शीर्षक 38249022 के अंतर्गत किया गया था लेकिन उसके बाद वर्गीकरण को बदल कर 38249922 में कर दिया गया है। यह यह नोट करना संगत है कि दर्शाया गया सीमा

शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है। विचाराधीन उत्पाद का आयात विभिन्न शीर्षों जैसे -38249090, 38249990, 28429090, 28269000, 28399090 और 28421000 के अंतर्गत किया गया है।

- v. चूंकि विचाराधीन उत्पाद का आयात विभिन्न संहिताओं के अंतर्गत किया जा रहा है, प्राधिकारी कृपया इन सांकेतिक संहिताओं का उल्लेख शुल्क तालिका में भी करें। केवल शुल्क तालिका की विषय वस्तु इस संबंध में संगत है। 'विचाराधीन उत्पाद' से संबंधित पैरा में उल्लिखित कोई भी बात परंतु जिसका उल्लेख शुल्क तालिका में नहीं किया गया है संभवतः वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करते समय अपेक्षा की जा सकती है। पोर्ट पर सीमा शुल्क के प्राधिकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर ही भरोसा करते हैं और विचार करते हैं। इस कारण से यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि शुल्क तालिका अपने आप में इन सभी स्पष्टीकरण को शामिल करे।
- vi. काफी बड़ी संख्या में आयात एक समर्पित संहिता के होने के बावजूद इस प्रकार की संहिताओं के अंतर्गत हो रही है। प्रवचना की संभावना बहुत अधिक हो जाती है यदि संगत संहिताओं का उल्लेख सीमा शुल्क अधिसूचना में नहीं किया गया हो।
- vii. जी सी एम आई एल डिटर्जेंट उद्योग के उपयोग के लिए और निरमा, घड़ी ज्योति लैब और पी एंड जी सहित भारत में सभी प्रमुख डिटर्जेंट निर्माताओं को नियमित आधार पर आपूर्ति करने के लिए जियोलाइट ए4 का उत्पादन करता है। जी सी एम आई एल उत्पाद चीन के उत्पादकों सहित सभी अन्य उत्पादकों से मेल खाता है। गुणवत्ता अस्वीकार्य होने के संबंध में जी सी एम आई एल और एच यू एल के बीच सूचना दर्शाते हुए एक्जीविट्स से संबंधित संलग्नक गोपनीयता का दावा करते हुए याचिका कर्ता को नहीं दर्शाया गया है। जी सी एम आई एल को प्रस्तुत किए गए नमूने के परिणामों के संबंध में जैसा कि एचयूएल द्वारा दावा किया गया है, कोई तकनीकी आकड़ा प्राप्त नहीं हुआ है और इस संबंध में केवल गलत दावे किए गए हैं।
- viii. गुणवत्ता नियंत्रण किसी उत्पाद को बाहर किये जाने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है। डी एस एम इंडैमिटशू लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेसटेट के निर्णय का संदर्भ लिया गया है।

ख.2 हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण नीचे दिया गया है:
 - i. उत्पाद के कार्य क्षेत्र में वे उत्पाद शामिल नहीं हैं जिसका उत्पादन और निर्माण याचिकाकर्ता द्वारा वाणिज्यिक रूप से नहीं किया जा रहा है। अतः आयात किए गए उत्पाद और घरेलू उद्योग के उत्पाद को 'समान वस्तु' के रूप में नहीं माना जा सकता है।
 - ii. याचिकाकर्ता एचयूएल द्वारा अपेक्षित तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार जियोलाइट ग्रेड 4ए का निर्माण एवं वाणिज्यिक रूप से आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। इस कारण से जियोलाइट ग्रेड 4ए के विनिर्देशनों को बाहर किए जाने का अनुरोध किया जाता है जो एचयूएल के विनिर्देशनों दी गई भारी घनत्व और मात्रा से मेल खाता है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. विचाराधीन उत्पाद सिन्थेटिक जियोलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड) है। जियोलाइट सुपरिभाषित संरचनाओं के साथ सूक्ष्म छेद वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सामान्य तौर पर उसमें उनके ढांचा और कैटियन में सिलिकॉन, अल्युमीनियम और ऑक्सीजन होता है, उनके छेदों के भीतर पानी और / अथवा अन्य मॉल्यिक्यूल होता है। कई प्राकृतिक रूप से खनिज पदार्थ के रूप में होते हैं और उनका विस्तार से खनन विश्व के कई भागों में किया जाता है। अन्य सिन्थेटिक होते हैं और उनका विभिन्न उद्योगों में विशिष्ट उपयोगों के लिए वाणिज्यिक रूप से निर्माण किया जाता है। जियोलाइट का सामान्य सूत्र एन ए एक्स [(एएलओ2) x (एसआईओ2) वाई].जेड एच 2 ओ के रूप में दिया गया है।
7. विचाराधीन उत्पाद प्राथमिक रूप से जल को कोमल बनाने के रूप में एक डिटर्जेंट बिल्डर के रूप में कार्य करता है जिसके फलस्वरूप जल मृदु हो जाता है जो समान सफाई प्रयास के लिए कम साबुन की खपत करता है क्योंकि कैल्शियम इयन को दूर करने के लिए साबुन बर्बाद नहीं होता है।
8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत आता है। संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण याचिका दायर करने के समय सीमा शुल्क उप शीर्षक 38249022 के अंतर्गत किया गया था लेकिन उसके बाद वर्गीकरण को बदल कर 38249922 में कर दिया गया है। आगे यह नोट किया जाता है कि है कि इस उत्पाद का आयात विभिन्न शीर्षों जैसे 38249090, 38249990, 28429090, 28269000, 28399090 और 28421000 के अंतर्गत भी

किया जा रहा है। इसको देखते हुए, ऐसे सभी रिपोर्ट किए गए शीर्षकों को भी वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। किसी भी मामले में दर्शाया गया सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।

9. एच यू एल के इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद अपेक्षित उपयोग के लिए सही नहीं हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एच यू एल को विशिष्ट तौर पर अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। जबकि कंपनी द्वारा कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराया कि एच यू एल ने यह सिद्ध नहीं किया है कि किस प्रकार से दो याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। उसको देखते हुए और घरेलू उद्योग द्वारा रिकार्ड पर दिए गए साक्ष्य पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि संबद्ध देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु प्रमुख विशेषताओं जैसे वस्तुओं की भौतिक और रसायनिक लक्षण, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में संबद्ध देश से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।

10. इस प्रकार से, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु पाटन रोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

ग **घरेलू उद्योग का कार्य क्षेत्र और स्थिति**

ग.1 **घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

11. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- यह याचिका मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लि. और मैसर्स कैमिकल इंडिया द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देश के किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है और न ही याचिकाकर्ताओं ने नियम 2(ख) के आशय से विचाराधीन का उत्पाद आयात किया है। याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन होता है। इस कारण से याचिकाकर्ताओं ने पाटन रोधी नियमावली के आशय से घरेलू उद्योग के स्थान की आवश्यकता को पूरा किया गया है।
- याचिकाकर्ता संगत अवधि के दौरान भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र उत्पादक है। याचिकाकर्ता की बाजार सूचना के अनुसार, घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है। अन्य उत्पादक अर्थात् नाल्को और गुजरात मल्टी गैस बेस कैमिकल्स प्रा.लि. जो पूर्व में इसका उत्पादन करने के लिए ज्ञात थे, से संपर्क याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता को इन कंपनियों द्वारा उत्पादन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। उनमें से किसी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद उत्तर नहीं दिया है और इस प्रकार से यह माना गया था कि याचिकाकर्ता घरेलू बाजार में एक मात्र घरेलू उत्पादक है। यद्यपि प्राधिकारी इस संबंध में जांच कर सकते हैं और आगे की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यदि इन कथित अन्य उत्पादक द्वारा अभी भी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तब याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन अभी भी कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रहेगा।

ग.2 **हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण**

12. इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र उत्पादक होने का दावा गलत ढंग से किया है जब उन्होंने स्वयं बहु अन्य उत्पादक जैसे नाल्को और गुजरात मल्टी गैस बेस कैमिकल्स प्रा.लि. जो उसके उत्पादन में शामिल हैं के होने को स्वीकार किया है।
- आवेदकों का संपूर्ण उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं हो सकता है। इसमें नाल्को और गुजरात मल्टी गैस बेस कैमिकल्स प्रा.लि. के उत्पादन को शामिल किया जाना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लि. और मैसर्स कैमिकल इंडिया द्वारा यह आवेदन दायर किया गया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक भारत में किसी आयातक और संबद्ध देश के किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है और न ही उन्होंने नियम 2(ख) के आशय से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।
14. इस दावे के संबंध में कि संबद्ध वस्तु के अन्य भारतीय उत्पादक अर्थात् नाल्को और गुजरात मल्टी गैस बेस केमिकल्स प्रा.लि. हैं, यह नोट किया जाता है कि आवेदकों द्वारा अन्य भारतीय उत्पादकों के संभावित उत्पादन, यदि कोई हो, के संबंध में उनके द्वारा किये गए बार बार प्रयासों को दर्शाते हुए साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि, कोई भी अन्य कंपनी अपने संभावित उत्पादन के संबंध में आगे नहीं आयी हैं। संगत सूचना संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण से भी मांगी गई थी। रिकार्ड पर कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है जो संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक द्वारा उत्पादन को दर्शाता हो। उसको देखते हुए प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है।
15. इस प्रकार से यह निर्धारित किया गया है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संबंध 'घरेलू उद्योग' होता है और उनके द्वारा दिया गया आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से दिए गए आवेदन के रूप में माना गया है। इसके अलावा, यह आवेदन पाटन रोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत 'स्थान' की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ. विविध अनुरोध**घ.1 घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

16. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :
- मूल एन सी वी याचिका और लाभ एवं हानि तथा बिक्री की लागत के संबंध में सर्वप्रथम अद्यतित याचिका के बीच आंकड़ों में अंतर्गत केवल जांच की अवधि में है और यह प्राधिकारी द्वारा मार्च, 2017 से जुलाई, 2017 तक जांच की अवधि के विस्तार के परिणाम स्वरूप हुआ है। दूसरी अद्यतित सूचना, वर्ष 2013-14 के लिए दर्शाए गए लागत घरेलू उद्योग की वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए कैमिकल्स इंडिया द्वारा उत्पादन को फिर से शुरू करने के मद्दे नजर सामान्य बनाया गया है। बाजार हिस्से के संबंध में आंकड़ों में अंतर इसलिए हैं क्योंकि याचिका दायर करने के समय गौण आंकड़ों का उपयोग किया गया था जबकि डी जी सी आई एंड एस के पास लेनदेन-वार आंकड़ों के साथ अद्यतित सूचना प्रस्तुत की गई थी।
 - लेनदेन-वार आयात आंकड़े सार्वजनिक फाइल में रखे जाने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। घरेलू उद्योग में लेनदेन-वार आंकड़ों में दिए गए विवरण के आधार पर तथा विचाराधीन उत्पाद के आयातक के बारे में घरेलू उद्योग की जानकारी के आधार पर एच एस संहिता 38249022 के अंतर्गत आने वाले अन्य मदों से डिटर्जेंट ग्रेड जिओलाइट को अलग किया है। प्राधिकारी इस सूचना को लेनदेन वार डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों में दिए गए आयातकों के नाम के साथ इस सूचना का संबंध निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना से स्थापित कर सकते हैं।
 - पहुंच कीमत, याचिकाकर्ताओं, अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा, संबद्ध आयात और गैर संबद्ध आयात के प्रकट न किए जाने के संबंध में दिए गए तर्क का कोई महत्व नहीं है क्योंकि उसे पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। सभी संगत सूचना याचिका में तथा जांच की अवधि में परिवर्तन करने के उपरांत दायर की गई अद्यतित सूचना में दी गई है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए समायोजन घरेलू उद्योग को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार है और यह उस प्रथा के अनुरूप है जिसे प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया है। याचिकाकर्ता ने अद्यतित याचिका दायर करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के पर विश्वास किया है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि बढ़ा दी गई थी।
 - नाल्को की जिओलाइट 4ए का उत्पादन करने के लिए इसकी अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा के साथ साथ सोडियम एल्युमिनेट लिकर का उपयोग कर 20 प्रतिशत तक उत्पादन की लागत कम करने की क्षमता विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने और इसकी बिक्री करने की इसकी क्षमता में दर्शाई गई है। ऐसा सुना नहीं गया है कि कोई भी व्यापार जो इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त कर लिया हो और तब सृजित क्षमताओं की सीमा तक उत्पादन नहीं कर रहा हो। अन्य भारतीय उत्पादकों के प्रयोक्ताओं / उपभोक्ताओं का अपने आप में बीजकों का उत्पादन नहीं करना यह साक्ष्य देता है कि अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया गया है।
 - मूल याचिका में परिवर्तन और वाद की अद्यतित सूचना इसलिए है क्योंकि याचिका दायर करने के समय उपयोग की गई आयात आंकड़ों को गौण स्रोत से प्राप्त किया गया था जिसे बाद में डी जी सी आई एंड एस लेनदेन वार आंकड़ों में परिणत कर दिया गया था। इसके अलावा, डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़े जिनका संदर्भ लिया जा रहा

है, समर्पित संहिता के अलावा अन्य संहिताओं के अंतर्गत आने वाले सभी आयातों की सूचना नहीं देता है। डी जी सी आई एंड एस लेनदेन-वार आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जांच की अवधि में आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

- vi. घरेलू उद्योग में मात्रा संबंधी मानदंडों के लिए वास्तविक आंकड़ों के बारे में नहीं बताया है जबकि निर्यातकों ने निर्यात, बिक्री, उत्पादन से संबंधित सूचना सहित अपने आंकड़ों पर पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है लेकिन घरेलू उद्योग से उसकी मांग कर रहा है। कुछ संबंधित/समूह कंपनियों ने इन जांचों में भाग लेने तथा उत्तर देने के लिए इसे असंगत भी पाया है। गोपनीयता का दावा करने का मानदंड घरेलू उत्पादकों और निर्यातकों के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है।

घ.2 हितवद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

17. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- मूल याचिका, सर्वप्रथम अद्यतित सूचना और दूसरे अद्यतित सूचना में दिए गए आंकड़े और लागत – हानि, बिक्री की लागत और बाजार हिस्से में निरंतरता नहीं है।
- लेनदेन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के अलावा उत्पाद जो एच एस कोड 38249022 के अंतर्गत आता है, को विश्लेषण के प्रयोजन से लिया गया है। उसको देखते हुए आयात आंकड़ों को अलग अलग करने के लिए उपयोग की गई पद्धति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- गोपनीय बर्ताव के लिए अनुचित अनुरोध याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है: संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के बारे में वास्तविक आंकड़ों में बताया जाना है क्योंकि इसमें कोई गोपनीय सूचना नहीं है: उन्होंने याचिका कर्ताओं, अन्य उत्पादकों, संबद्ध आयातों, गैर संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से को भी उपलब्ध नहीं कराया है।
- सभी आर्थिक मानदंडों, आयातों, सामान्य मूल्य, बाजार हिस्सा, पाटन मार्जिन और टी-बी-टी आयात आंकड़ों की सॉफ्ट कॉपी (एक्सल फाइल) के संबंध में सूचना अप्रैल, 2016 से जून, 2017 तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- नाल्को की जिओलाइट 4ए का उत्पादन करने के लिए इसकी अति आधुनिक उत्पादन क्षमता के साथ साथ सोडियम एल्यूमिनेट लिकर का उपयोग कर 20 प्रतिशत तक उत्पादन की लागत कम करने की क्षमता पर विचार विचाराधीन उत्पादन का उत्पादन करते समय किया जाना चाहिए था और नाल्को को वर्तमान मामले में एक हितवद्ध पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था; यह संदर्भ यूरोपीय समुदाय – चीन से कुछ लौह एवं इस्पात फास्टनर पर निश्चयात्मक पाटन रोधी उपाय, डब्ल्यू टी / डी एस 397 / ए बी / आर के संबंध में है।
- चूंकि कथित पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य शियर एक्जिम सोल्यूशंस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर है और वह आयात में उछाल को दर्शाता है। आवेदक को आयात आंकड़ों के उचित मूल्यांकन के लिए डी जी सी आई एंड एस आंकड़े अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।
- आवेदक ने केवल 12 महीने के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं जो जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना के अनुसार पूर्ण नहीं है; वर्तमान जांच के आरंभन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना में विचार की गई क्षति की अवधि और जांच की अवधि के लिए सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित है।
- आवेदकों के आयात आंकड़े वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से बिल्कुल अलग है।
- आवेदकों के कार्य निष्पादन के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। वह क्षति के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों को छुपाने की सीमा तक चला गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच के संबंध में अनेक मुद्दे उठाए हैं और उसकी जांच और उसका समाधान नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

- मूल याचिका और प्रथम एवं द्वितीय अद्यतित सूचना में निरंतरता नहीं होने संबंधी तर्क के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि को बढ़ाया गया था और अप्रैल 2016-जून 2017 (15 महीने) की अवधि शामिल की गई थी। बढ़ाई गई जांच की अवधि को देखते हुए उद्योग की अद्यतित सूचना डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत की गई थी जबकि, इस याचिका को मूल रूप में गौण आयात

- आंकड़ों के आधार पर दायर किया गया था। द्वितीय अद्यतित सूचना घरेलू उद्योग द्वारा आयात संबंधी पद्धति और घरेलू उद्योग की क्षति संबंधी सूचना शामिल करते हुए और घरेलू उत्पादक में से एक द्वारा स्थापित क्षमता को देखते हुए मानदंड संबंधी लागतों के आधार पर की गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आंकड़े अलग अलग हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना में कोई अनिश्चय नहीं है।
- ii. लेनदेन-वार आंकड़ों को उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा उसी संहिता के अंतर्गत आने वाले विचाराधीन उत्पाद को छोड़कर अन्य उत्पादों और जिन्हें क्षति के विश्लेषण के प्रयोजन से अभी लिया जाना है से संबंधित तर्क के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लेनदेन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हें सार्वजनिक फाइल में रखा गया है। डिटर्जेंट ग्रेड जिओलाइट को लेनदेन-वार आंकड़ों में दिए गए विवरण के आधार पर अलग अलग किया गया है। इस आंकड़े को निर्यातकों के आंकड़े के साथ इसकी प्रश्नावली के उत्तर से मिलाया गया है और यह पाया गया है कि डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अंतर्गत सूचित की गई आयातों की *** मी.ट. मात्रा की तुलना में, चीन में निर्यातकों द्वारा सूचित किए गए आयात मात्रा *** मी.ट. है।
 - iii. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की गई अनुचित गोपनीयता के दावे के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे की जांच की गई है और इसे पाटन रोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार स्वीकार्य पाया गया है।
 - iv. एक वैकल्पिक प्रक्रिया जिसका उपयोग नाल्को द्वारा किया गया है और जिस पर घरेलू उद्योग द्वारा विचार भी किया गया था संबंधी किए गए दावे के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ठोस साक्ष्य नाल्को द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसको देखते हुए, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि नाल्को संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में शामिल नहीं है और इस कारण से वैकल्पिक उत्पादन की प्रक्रिया के संबंध में दावे पर विचार नहीं किया जा रहा है।
 - v. इन दावों के संबंध में कि यह आंकड़े केवल 12 महीने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं और इस प्रकार से वर्तमान जांच के लिए विचार की गई जांच की अवधि के लिए जांच आरंभन सकारात्मक सूचना के आधार पर नहीं हुई है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी सकारात्मक सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग को पाटन से हुई क्षति के तथ्य से अपने आप संतुष्ट थे। जांच की अवधि एक तिमाही तक बढ़ाई गई है, इस प्रकार से जांच की अवधि का एक बड़े हिस्से की जांच आरंभन के प्रयोजन से की गई थी। ऐसा जांच आरंभन की तिथि के करीब जांच की अवधि को बनाने के उद्देश्य से किया गया था ताकि जांच की अवधि को बढ़ाया जा सके। यह भी नोट किया गया है कि इसे जांच की प्रक्रिया के दौरान भी बदला जा सकता है क्योंकि उद्देश्य वस्तुपरक आकलन करने के लिए एक उपयुक्त अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन का मूल्यांकन करना है। किसी भी मामले में, पाटन और क्षति के तथ्य को वर्तमान जांच की अवधि में सिद्ध की गई है जिसे संगत स्थानों पर इस अधिसूचना से देखा जा सकता है।
 - vi. घरेलू उद्योग के आयात संबंधी आंकड़े के डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों से अलग होने संबंधी तर्क के बारे में, यह देखा गया है कि डी जी सी आई एंड एस के लेनदेन-वार आंकड़ों के उपलब्ध नहीं होने के कारण, इस आवेदन को गौण स्रोत से प्राप्त किए गए आंकड़ों के आधार पर दायर किया गया था। इसे बाद में घरेलू उद्योग द्वारा डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किए गए लेनदेन-वार आंकड़ों के आधार पर अद्यतित किया गया था। प्राधिकारी ने अद्यतित आंकड़ों पर भी विचार किया है।

ड. बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव (एम ई टी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ड.1 घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

19. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ साथ नीचे दिए गए अनुसार अनुरोध किया:

- i. एक्सेशन प्रोटोकॉल के प्रावधानों में से एक प्रावधान 11 दिसम्बर, 2016 को समाप्त हो गया है। हालांकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी को चीन के उत्पादकों को नीचे दिए गए कारणों से गैर बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में कार्य करने वाले उत्पादक के रूप में विचार करते हुए वर्तमान जांच में आगे की कार्रवाई करनी चाहिए :
- ii. वर्तमान मामले में प्राधिकारी द्वारा विचार की गई जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से जून, 2017 (15 महीने) है।

- iii. जांच की अवधि के निर्धारण का उद्देश्य उस अवधि पर विचार करने के लिए है जब पाटन से होने वाली क्षति के मौजूद होने का दावा किया गया हो और उसे सिद्ध किया गया हो। वर्तमान मामले में जांच की अवधि का एक बड़ा हिस्सा चीन के एक्सेशन प्रोटोकाल के समाप्त होने के पूर्व पड़ता है और इस कारण से चीन को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना उपयुक्त होगा।
- iv. चीन के उत्पादकों को इस कारण से गैर बाजार अर्थव्यवस्था कंपनियों के रूप में माने जाने की आवश्यकता है कि चीन में लागतें और कीमतें जांच की अवधि के दौरान बाजार शक्तियों को उचित रूप में नहीं दर्शाया। अनुबंध-के पैरा 8 में उन मानदंडों का उल्लेख है जिस पर बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा देने के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- v. चूंकि चीन की कंपनियों को दिसम्बर, 2016 तक अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित कारणों से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया गया था, अतः याचिकाकर्ता यह अनुरोध करते हैं कि चीन के उत्पादकों को उस समय तक गैर बाजार अर्थव्यवस्था कंपनियों के रूप में माने जाने की आवश्यकता है जब तक जांच की अवधि में एक्सेशन प्रोटोकाल में उल्लिखित अवधि शामिल नहीं कर लिया गया हो।
- vi. चीन के उत्पादकों को गैर बाजार अर्थव्यवस्था परिवेश के अंतर्गत कार्यरत कंपनियों के रूप में माने जाने की आवश्यकता है और प्राधिकारी अनुबंध-I के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्रवाई कर सकते हैं।
- vii. सामान्य मूल्य का निर्धारण उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के तृतीय देश में समान वस्तु की कीमत के आधार पर इस कारण से नहीं किया जा सका कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता ने विधिवत् समायोजन भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने का दावा किया है।
- viii. चीन से पाटन मार्जिन न केवल बहुत अधिक है बल्कि वास्तविक भी है और इस प्रकार से भारत में विचाराधीन उत्पाद के बहुत अधिक पाटन का होना सिद्ध होता है। चीन के आयात की मात्रा क्षति की पूरी वर्तमान अवधि के दौरान बहुत अधिक रही है।
- ix. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए समायोजन उन्हें उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप है। निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है और प्राधिकारी सत्यापन के बाद और उनके उपयुक्त और सही पाए जाने की स्थिति में वास्तविक समायोजन पर विचार कर सकते हैं।
- x. घरेलू उद्योग ने परियोजना रिपोर्ट के आधार पर गुजरात क्रेडो मिनरल्स के लिए मानदंड संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। इस याचिका में दिए गए आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति को नहीं दर्शाते हैं, बल्कि यह मानदंड संबंधी आंकड़ों के आधार पर अपेक्षाकृत बहुत कम क्षति है।

ड.2 **हितबद्ध पक्षकारों के दृष्टिकोण**

20. सामान्य मूल्य, निर्यात की कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग में निवल निर्यात कीमत से समायोजन का दावा किया है परंतु उसके लिए कोई साक्ष्य/औचित्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- ii. वर्तमान जांच को सामान्य मूल्य का निर्धारण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उसका निर्धारण चीन जन गण में संबद्ध वस्तुओं की लागत और घरेलू बिक्री से किया जाना चाहिए था क्योंकि चीन जन गण के एक्सेशन प्रोटोकाल के पैरा-15 (क) (ii) के प्रावधानों को रद्द कर दिया गया है। वर्तमान मामले में कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को तृतीय देश के चयन के बारे में सूचना नहीं दी गई है; कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि क्या याचिकाकर्ताओं ने आदर्शतम क्षमता का उपयोग नहीं किए जाने के कारण कोई समायोजन किया है।
- iii. घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक याचिकाकर्ता एक नया निगमित प्रतिष्ठान है, जिसे उत्पादन की उच्च लागत का सामना करना पड़ रहा है।

ड.3 **प्राधिकारी द्वारा जांच**

ड.3.1 बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच

21. जांच आरंभन के चरण में, याचिकाकर्ताओं ने चीन जन गण को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मान कर इस मान्यता के साथ आगे की कार्रवाई की। जांच आरंभन के बाद, प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों / निर्यातकों को जांच आरंभन की नोटिस का जवाब देने तथा इस तथ्य के निर्धारण से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़े / सूचना को सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी जात उत्पादकों / निर्यातकों को प्रश्नावली की प्रतियां भेजी।
22. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने वर्तमान मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में 'बाजार अर्थव्यवस्था' प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। इस असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी चीन के उत्पादकों / निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में सक्षम नहीं है।
23. घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में लागतों अथवा कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी को कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है। इस कारण से प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

ड.3.2 **चीन जन गण में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**

24. भारत में चीन जन गण से आयात किए गए संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य को कच्चे मालों और यूटिलिटी की सर्वोत्तम आदर्शतम खपत और उत्पादन की लागत पर उचित लाभ सहित परिवर्तन लागत, ब्याज, एस जी ए आदि का सर्वश्रेष्ठ अनुमान पर विचार करते हुए तय किया गया है।

ड.3.3 **चीन जन गण के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण**

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन गण के पाँच निर्यातकों में प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत की है जिसका उपयोग निर्यात कीमत और अलग अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए किया जा सकता है।
- क. मैसर्स इनर मंगोलिया रिसिंग रिसाइकलिंग रिसोर्स कंपनी लि.।
 - ख. मैसर्स तियानजिन गर्कविन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि.
 - ग. मैसर्स चालको सानडोंग एडवांस्ड मटीरियल कंपनी लि.।
 - घ. मैसर्स चालको क्विंगडाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि.
 - ड. मैसर्स चालको जिबो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि.

26. अतः प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा दिए गए उत्तर का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया है:

मैसर्स इनर मंगोलिया रिसिंग रिसाइकलिंग रिसोर्स कंपनी लि. (उत्पादक) और मैसर्स तियानजिन गर्कविन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि. (निर्यातक) चीन जन गण

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिसिंग ने ट्रेडर गर्कविन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि. के माध्यम से भारत में संबद्ध वस्तुओं का *** मी.ट का निर्यात किया है। उन्होंने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण लागत, बैंक शुल्क, मूल्य वर्धित कर और भारतीय निर्यातक को कमीशन के कारण हुए खर्च का दावा किया है। उसकी अनुमति उचित सत्यापन के बाद दी गई है। तदनुसार प्राधिकारी ने *** यू एस डॉलर / मी.ट. के रूप में एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

मैसर्स चालको सानडोंग एडवांस्ड मटीरियल कंपनी लि. ('चालको ए एम') (उत्पादक), मैसर्स चालको क्विंगडाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि. (चालको क्विंगडाओ) (निर्यातक) और मैसर्स चालको जिबो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि. (चालको जिबो) (निर्यातक) चीन जन गण

28. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चालको ए एम ने संबंधित ट्रेडर चालको क्विंगडाओ के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का *** मी.ट. और एक अन्य ट्रेडर से संबंधित ट्रेडर नामतः चालको जिबो के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का *** मी.ट निर्यात किया है। उन्होंने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण लागत, बैंक शुल्क, मूल्य वर्धित कर और भारतीय निर्यातक को कमीशन के कारण हुए खर्च का दावा किया है। उसकी अनुमति उचित सत्यापन के बाद दी गई है। तदनुसार प्राधिकारी ने अन्य संबंधित ट्रेडर नामतः चालको जिबो के माध्यम से अपने निर्यात के लिए *** यू एस डॉलर / मी.ट. तथा अपने संबंधित ट्रेडर चालको क्विंगडाओ के माध्यम से निर्यात के लिए चालको ए एम के लिए *** यू एस डॉलर / मी.ट. के रूप में एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

ड.3.6 असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात की कीमत

29. चीन जन गण के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, निर्यात मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सी आई एंड एस के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर उसे उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर से सह संबंध स्थापित करने के बाद किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित निर्यात कीमत और उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा सूचित निर्यात की कीमत में कोई बड़ा अंतर नहीं है। चूंकि ये सी आई एफ निर्यात की कीमत है अतः इनका समायोजन एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पोर्ट खर्च, बैंक शुल्क, अंतर्देशीय भाड़ा, मूल्य वर्धित कर और कमीशन जैसे खर्च के लिए किया गया है।

ड.3.7 पाटन मार्जिन का निर्धारण

30. संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण सामान्य मूल्य की तुलना संबद्ध वस्तुओं के लिए एक्स फैक्ट्री स्तर पर निर्यात की कीमत से करने के बाद की गई है। नीचे दी गई तालिका उत्तर देने वाले निर्यातकों और संबद्ध देश के लिए औसत भारत मूल्य को दर्शाती है:

तालिका

| उत्पादक | निर्यातक | सामान्य मूल्य (यू एस डॉलर / मी.ट) | निवल निर्यात कीमत (यू एस डॉलर / मी.ट) | पाटन मार्जिन (यू एस डॉलर / मी.ट) | पाटन मार्जिन (प्रतिशत) | पाटन मार्जिन (प्रतिशत रेंज) |
|--|--|---|---|--|---------------------------|--------------------------------|
| मैसर्स इनर मंगोलिया रिसिंग रिसाइकलिंग रिसोर्स कंपनी लि.(आई एम आर आर आर सी एल) | मैसर्स तियानजिन गर्कविन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि.(टी जी आई टी सी एल) | *** | *** | *** | *** | 65-75% |
| मैसर्स चालको सानडोंग एडवांस्ड मटीरियल कंपनी लि (सी एस ए एम सी एल) | मैसर्स चालको जिब्रो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि.(सी जी आई टी सी एल) | *** | *** | *** | *** | 85-95% |
| मैसर्स चालको सानडोंग एडवांस्ड मटीरियल कंपनी लि (सी एस ए एम सी एल) | मैसर्स चालको क्विंगडाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.लि. (सी क्यू आई टी सी एल) | *** | *** | *** | *** | 80-90% |
| अन्य | अन्य | *** | *** | *** | *** | 100-110% |

31. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन भारत में सभी आयातों के संबंधों में नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।
- च. क्षति और कारणात्मक संबंध
- च.1 घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण
32. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग में नीचे दिए गए अनुसार अनुरोध किया है:

- i. वास्तविक क्षति की जांच आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच केवल प्रवृत्ति का विश्लेषण है और इस प्रकार के विश्लेषण के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष भ्रामक हो सकता है और वस्तुपरक नहीं होगा। प्रवृत्ति में वृद्धि अथवा कमी केवल क्षति का माप करने के लिए मानदंड है। घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति की जांच में क्षति की अवधि के भीतर हुई घटनाओं पर विचार करना चाहिए और यह कि क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से 2013-14 की उपेक्षा की जानी चाहिए।
- ii. याचिका कर्ता कंपनियों में अन्य भारतीय उत्पादकों तक पहुंच बनाने के लिए पर्याप्त और भरपूर प्रयास किए हैं। हालांकि, उनमें से किसी ने बार बार किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद उत्तर नहीं दिया है। याचिका कर्ताओं ने भी उसके संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से संपर्क किया था। बाजार सूचना के आधार पर, अन्य उत्पादक संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में शामिल नहीं हैं।
- iii. जी सी एम आई एल की लागत और लाभ / हानि पर विचार परियोजना रिपोर्ट के अनुसार मानदंड संबंधी क्षमता उपयोग के अनुसार किया गया है। जी सी एम आई एल के आंकड़ों पर विचार मानदंड संबंधी स्तरों पर नहीं किया गया है। जी सी एम आई एल को हुई वास्तविक क्षति उस क्षति से बहुत अधिक है जिसे क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से लिया गया है। बढ़े हुए उत्पादन और बिक्री आंकड़े जी सी एम आई एल द्वारा उत्पादन शुरू करने के कारण हैं। जिस कीमत क्षति का दावा किया गया है वह संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुआ है।
- iv. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 7 % की वृद्धि के बावजूद, यह अभी भी बहुत कम है यद्यपि इसमें संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है जबकि आयात का बाजार हिस्सा बहुत अधिक है। जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि के साथ आयातों में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई। उत्पादन और बिक्री की तुलना में आयात लगभग 1000% रहता है। मांग में आयातों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में 93 % थी।
- v. 2013-14 से वास्तविक लाभप्रदता की तुलना सही तस्वीर नहीं दर्शाएगी क्योंकि एक याचिका कर्ता कंपनी ने अभी उत्पादन फिर से शुरू किया था और वह भी बहुत कम स्तर पर। प्राधिकारी सामान्य उत्पादन स्तरों पर ओवरहेड लागतों पर विचार कर लाभप्रदता पर विचार कर सकते हैं।
- vi. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत, बिक्री की कीमत और क्षति रहित कीमत के स्तर से कम है। कीमत में कटौती में भी वृद्धि हुई है। बिक्री की लागत में समान अवधि में गिरावट के बिना जांच की अवधि में आयात की पहुंच कीमत में गिरावट आई। आयात कीमत जो क्षति की अवधि के प्रारम्भ में 500 यू एस डॉलर/ मी.ट से थोड़ा कम थी, बढ़ कर 2013-14 के मध्य में जब कैमिकल्स इंडिया ने अपना उत्पादन और बिक्री बढ़ाया, 500 यू एस डॉलर/ मी.ट से ऊपर के स्तर तक पहुंच गई। हालांकि, उसके बाद कीमतों में तेजी से गिरावट आई और यह 320 यू एस डॉलर/ मी.ट हो गया। आयात की कीमत में लगभग 180 यू एस डॉलर/ मी.ट तक गिरावट इस उत्पाद की प्रकृति में बहुत अधिक है। कच्चे माल के कारण लागत में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। चीन के उत्पादकों ने लगभग 40 प्रतिशत तक अपनी कीमतों में कटौती की है, जिसका एक मात्र कारण जी सी एम आई एल द्वारा उत्पादन की शुरुआत और कैमिकल्स इंडिया द्वारा उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि है।
- vii. कीमत में कटौती की सीमा जी सी एम आई एल द्वारा उत्पादन की शुरुआत के साथ जांच की अवधि में बढ़ गई है जिसे प्राधिकारी के पास प्रस्तुत गोपनीय आंकड़ों से देखा जा सकता है। निवेश पर आय में जांच की अवधि में बहुत नीचे स्तर तक गिरावट आई। लाभ और निवेश पर आय को बहुत अधिक निम्न उत्पादन आंकड़ों के लिए उपयुक्त रूप से मानदंड के अनुरूप किया जाना है और तभी कोई उचित तस्वीर सामने आयेगी।
- viii. जी सी एम आई एल के लिए स्टार्ट-अप के कारण कोई असामान्य लागत को क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से मानदंड के अनुरूप बनाया गया है। जी सी एम आई एल की वार्षिक रिपोर्ट से विभिन्न मानदंडों की सूची दर्शाते हुए कथित दावे इस प्रकार से खोखले हैं।
- ix. घरेलू उद्योग की बाद के वर्षों की तुलना में आधार वर्ष में स्थिति घरेलू उद्योग की स्थिति का द्योतक है क्योंकि केवल कैमिकल्स इंडिया में बहुत सूक्ष्म स्तर पर आधार वर्ष में उत्पादन फिर से शुरू किया। आयातों का घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- x. मात्रा संबंधी मानदंडों जैसे बिक्री, उत्पादन और उपयोग में वृद्धि इस कारण से हुआ है कि कैमिकल्स इंडिया ने आधार वर्ष में बहुत कम स्तर पर उत्पादन किया था और जी सी एम आई एल ने जांच की अवधि के दौरान शुरु किया था और इस प्रकार से इन मानदंडों में स्वाभाविक वृद्धि दृष्टिगत हुई है।
- xi. उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद आदर्शतम स्तर से बहुत कम है। आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागतों और बिक्री की कीमतों के स्तर से बहुत कम है जिसके कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- xii. एक याचिकाकर्ता कंपनी ने आधार वर्ष से उत्पादन फिर से शुरु किया और वह यह आशा कर रहा था कि उत्पादन और बिक्री तथा लाभप्रदता में वृद्धि होगी लेकिन पाटित आयातों ने इसे वैसा होने से रोक दिया। आयात की कीमत में तब बहुत अधिक गिरावट आई जब जी सी एम आई एल ने जांच की। अवधि के दौरान उत्पादन शुरु किया। इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- xiii. मानदंड संबंधी कीमतों के बावजूद, घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हानि दर्शाता है। स्टार्ट-अप की कीमतों पर क्षति का दोष आरोपित करते हुए जब बार बार यह उल्लेख किया गया कि मानदंड संबंधी लागत जी सी एम आई एल के लिए लिया गया है, आवश्यक नहीं है। निर्यातकों को आयात की कीमतों में बहुत अधिक कटौती का अवश्य उत्तर देना चाहिए।
- xiv. लागत संबंधी सभी मानदंड मानक संबंधी आधार पर किया गया है ताकि एक उचित और वस्तुपरक विश्लेषण हो सके। दावा की गई क्षति ह्रास, मजदूरी अथवा ब्याज में खर्च में असामान्य वृद्धि के कारण नहीं हुई है।
- xv. कीमत में कटौती क्षति का कारण है और कीमत पर बिक्री घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को दर्शाता है। कम कीमत पर बिक्री के कारण लाभ, नगद लाभ और निवेश पर आय पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- xvi. कीमत में बहुत अधिक स्तर तक कटौती के फलस्वरूप घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनीकरण/दबाव प्रभाव पड़ा और इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को मानदंड संबंधी लागतों के स्तर से बहुत कम स्तर पर बिक्री कीमत रखने के लिए बाध्य होना पड़ा (और न कि वास्तविक लागतों पर) जिससे वित्तीय हानि हुई। बहुत अधिक कम कीमत स्तर पर आयात ने बाजार में घरेलू उद्योग के न्यायोचित हिस्सा का बहुत बड़ा भाग कब्जा कर लिया। आयातों के कारण स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- xvii. घरेलू उद्योग के माल भंडार में भी क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जांच की बाद की अवधि में, माल भंडार में लगभग 600 मी.ट तक वृद्धि हुई है।
- xviii. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री शून्य के करीब था और इस कारण से उसके बाद कोई वृद्धि सूचीबद्ध रूप में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में बहुत बड़ा उछाल दर्शाएगा।
- xix. मानक के अनुरूप लागतों को तय किए जाने के बाद यथा प्रस्तुत सूचना यह दर्शाती है कि बिक्री की लागत में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जबकि बिक्री की कीमत में गिरावट आई है। आयातों का पहुंच कीमत भी जांच की अवधि के दौरान बहुत तेजी से कम हुई है और यह घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री के स्तर से कम है। आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर बहुत अधिक दबावकारी प्रभाव पड़ रहा है। कम कीमत पर बिक्री क्षति को दर्शाने वाले कानून के अंतर्गत निर्धारित मानदंड नहीं है।
- xx. आयात मांग का 93 प्रतिशत होता है और घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी अन्य उत्पादक द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन का कोई साक्ष्य नहीं है।
- xxi. जी सी एम आई एल के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण मानदंड संबंधी उत्पादन के स्तर पर किया जा सकता है। घरेलू उद्योग कीमत में कटौती संबंधी विश्लेषण के लिए आदर्शतम कीमत के पीछे का तर्क समझ पाने में असमर्थ है क्योंकि इसमें आयातों की पहुंच कीमत और बिक्री कीमत के बीच अंतर शामिल है। किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए बिक्री की लागत को मानदंड के अनुरूप बनाया गया है।

च.2 **अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण**

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नीचे दिए गए अनुसार अनुरोध किया गया है:

- i. अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री जो बाजार हिस्से की गणना करने और याचिकाकर्ता द्वारा अन्य घरेलू उत्पादकों के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए उपयोगी है, नहीं है।
- ii. घरेलू उद्योग ने जी सी एम आई एल को हुई हानि और स्टार्ट-अप की लागतों को अधिक करने के लिए वर्तमान जांच में दोनों कंपनियों के लिए वास्तविक क्षति का दावा किया है; यह तथ्य कि जी सी एम आई एल ने हाल में उत्पादन शुरू किया है, का याचिकाकर्ताओं की सुविधा के अनुसार चयनित रूप से उपयोग किया गया है, हालांकि, कीमत संबंधी क्षति का आकलन करते समय, याचिकाकर्ताओं में जी सी एम आई एल को हुई प्रारंभिक क्षति तथा बढ़े हुए लागतों के संबंध में मुद्दों का रणनीतिक रूप से समाधान नहीं किया है।
- iii. याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 7 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
- iv. याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता में 2014-15 से तेजी से गिरावट होती रही है। आधार वर्ष से तुलना किए जाने पर लाभप्रदता में 2014-15 में 69 सूचकांक तक गिरावट आई जबकि पटुंच कीमत में उसी अवधि के दौरान 1 सूचकांक तक वास्तव में वृद्धि हुई है।
- v. यदि कीमत में कटौती का प्रभाव याचिकाकर्ताओं पर पड़ा तब आधार वर्ष से तुलना किए जाने पर जांच की अवधि में निवेश की आय में बहुत अधिक गिरावट होनी चाहिए थी जो वर्तमान वास्तविक मैट्रिक्स में स्थिति नहीं है। (निवेश पर आय क्षति की समग्र अवधि के लिए उसी रेंज में है)।
- vi. जांच की अवधि से जी सी एम आई एल के उत्पादन की शुरुआत के फलस्वरूप याचिकाकर्ताओं को क्षति हुई है। यह क्षति उन उच्च लागतों और हानियों के कारण हुई है जिन्हें वित्तीय लागतों, लघु अवधि की ऋण और व्यापार भुगतान योग्य राशि जैसे वित्तीय सांकेतिकों में दर्शाया गया है।
- vii. घरेलू उद्योग ने मूल याचिका की तुलना में नवीनतम फाइल में अनेक क्षति संबंधी मानदंडों के लिए पर्याप्त परिवर्तन के साथ और चयनित क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराया है जिसके कारण प्रतिवादी कोई सार्थक टिप्पणी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।
- viii. घरेलू उद्योग को निम्नलिखित मानदंडों- क्षमता उपयोग, उत्पादक और क्षमता जिसमें क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है, में क्षति नहीं हुई है; घरेलू बिक्री और बाजार के हिस्से में बहुत अधिक उछाल देखा गया है और यह उद्योग को किसी क्षति को नहीं दर्शाता है; मजदूरी और कर्मचारियों की संख्या को भी गोपनीय रखा गया है क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई है, इन मानदंडों में भी वृद्धि हुई है; उत्पादकता संबंधी सूचना गोपनीय है क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई, इसमें सुधार भी अवश्य हुआ होगा; माल भंडार का विश्लेषण करने का सही तरीका अंतिम माल भंडार की तुलना घरेलू उद्योग द्वारा की गई घरेलू बिक्री से की जानी है जैसा कि ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2011(270) ई.एल.टी. 696 (टी आर आई-डी ई एल) के मामले में माननीय सेसटेट द्वारा निर्धारित की गई थी; घरेलू उद्योग के विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ix. कीमत में कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि घरेलू उद्योग में क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया और इस प्रकार से यह उत्पाद के लिए कीमत को कम ही करेगा; उस पर आयातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके साथ ही संबद्ध देश के आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई।
- x. हास, मजदूरी और ब्याज की लागत में वृद्धि संबद्ध देश से आयातों के कारण नहीं बल्कि उच्च निवेश से नई मशीनरी की खरीद के कारण हुई है; घरेलू उद्योग की लागत पर क्षमता पर वृद्धि का प्रभाव इस का विश्लेषण किए जाने के लिए भी अपेक्षित है जब संयुक्त राज्य अमेरिका से चाइना-ग्रेन ओरियेन्टेड फ्लैट रॉलड इलेक्ट्रिकल स्टील में विश्व व्यापार संगठन के पैनल द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार क्षमता में वृद्धि हुई है।
- xi. आयातों में वृद्धि क्षति का कारक नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है; क्षति का कोई निष्कर्ष कीमत में कटौती और कम कीमत पर कटौती के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि दोनों क्षति के कारक नहीं हैं।
- xii. घरेलू उद्योग के माल भंडार में गिरावट आई है; उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्से में वृद्धि अप्रत्याशित है।

- xiii. आयातों द्वारा कीमत पर प्रभाव पड़ने का कोई साक्ष्य नहीं है और ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ रही है, इस कारण से कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। लागत में वृद्धि और क्षमता में वृद्धि तथा परस्पर प्रतियोगिता के कारण क्षति हुई है।
- xiv. घरेलू उद्योग क्षति के दावे और आर्थिक मानदंडों जैसे निवल बिक्री प्राप्ति, नगद प्रभाव, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव को सिद्ध करते हुए कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं करा पाया है।
- xv. घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं की बिक्री और उत्पादन में उस दर से वृद्धि हुई है जो मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक है जबकि आयातों में वृद्धि तुलनात्मक रूप से उतनी अधिक नहीं हुई है।
- xvi. कीमत न्यूनीकरण/कीमत पर दबाव नहीं हुआ है क्योंकि बिक्री की लागत में गिरावट आई और कम कीमत पर बिक्री का कोई दावा नहीं है।
- xvii. घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं की कीमत के संबंध में परस्पर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है और वह अन्य उत्पादकों की भागीदारी नहीं होने से स्पष्ट है।
- xviii. क्षति रहित कीमत का निर्धारण मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लि. को छोड़कर अन्य उत्पादकों से प्राप्त आंकड़ों पर विचार करने के बाद किया जा सकता है। उसका वैकल्पिक विश्लेषण किया जाना चाहिए। स्टार्ट-अप लागत के कारण उत्पादन की लागत अधिक होने की वजह से, प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वह कीमत में कटौती का निष्पक्ष निर्धारण करने के लिए उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत का समायोजन करें।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा भी किए गए अनुरोधों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने पाटन रोधी नियमावली के अनुसार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर उपयुक्त रूप से विचार करने के बाद घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की है।
35. प्राधिकारी द्वारा इसके अंतर्गत किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है। इसमें मामूली गणना त्रुटि में सुधार शामिल है, जिसे पहले जारी किए गए प्रकटीकरण वक्तव्य पर टिप्पणियों में बताया गया था।
36. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के अनुबंध II (iv) के अनुसार इस प्रकार के सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि पर विचार किया है।
37. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के कारण क्षति और पाटन के संभावित पहलुओं की जांच करने की कार्रवाई करने के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की कार्रवाई करते हैं।

च.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

(क) माँग और बाजार हिस्सेदारी

38. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के उद्देश्य से भारत में उत्पाद की माँग अथवा प्रत्यक्ष उपभोग को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित की गई माँग नीचे तालिका में दी गई है।

| विवरण | इकाई | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | पीओआई- ए |
|---------------------------------|------|---------|---------|---------|----------|
| माँग | | | | | |
| डीआई की बिक्री | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री | एमटी | - | - | - | - |
| संबद्ध देशों से आयात | एमटी | 24,929 | 25,927 | 31,022 | 31,809 |
| अन्य देशों से आयात | एमटी | 54 | 77 | 53 | 75 |

| कुल माँग/उपभोग | एमटी | *** | *** | *** | *** |
|----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| माँग में बाजार हिस्सेदारी | | | | | |
| डीआईए की बिक्री | % | 0% | 1% | 4% | 7% |
| अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री | % | 0% | 0% | 0% | 0% |
| संबद्ध देशों से आयात | % | 100% | 99% | 96% | 93% |
| अन्य देशों से आयात | % | 0% | 0% | 0% | 0% |
| कुल माँग/उपभोग | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

39. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि नुकसान की पूर्ण अवधि के दौरान पीयूसी की माँग बढ़ी है। बाजार में अधिकतम हिस्सेदारी संबद्ध देशों के आयात की है। देश में पाटन के कारण डीआई के पास पर्याप्त क्षमताएँ होने के बावजूद माँग में डीआई की हिस्सेदारी बहुत कम है।

(ख) आयात की मात्रा और संबद्ध देश की हिस्सेदारी

40. पाटित आयात के संदर्भ में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा उपभोग की तुलना में पाटित आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

| विवरण | इकाई | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | पीओआई- ए |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| मात्रा | | | | | |
| संबद्ध देश | एमटी | 24,929 | 25,927 | 31,022 | 31,809 |
| अन्य देश | एमटी | 54 | 77 | 53 | 75 |
| कुल आयात | एमटी | 24,983 | 26,004 | 31,076 | 31,884 |
| आयातों में बाजार हिस्सेदारी | | | | | |
| संबद्ध देश | % | 99.78 | 99.70 | 99.83 | 99.77 |
| अन्य देश | % | 0.22 | 0.3 | 0.17 | 0.23 |
| कुल आयात | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध देश का आयात | % | 830970 | 9804 | 2320 | 1336 |
| उपभोग की तुलना में संबद्ध देश का आयात | % | 100 | 99 | 96 | 93 |
| कुल आयात की तुलना में संबद्ध देश का आयात | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

41. यह नोट किया गया है कि नुकसान की पूर्ण अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप से संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है और पीओआई में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नुकसान की पूर्ण अवधि के दौरान अन्य देशों से आयात नगण्य है।

42. पीओआई में जीसीएमआईएल द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने और केमिकल्स इंडिया द्वारा उत्पादन पुनः शुरू किए जाने को ध्यान में रखते हुए भारतीय उत्पादन और उपभोग के संदर्भ में आयात में कमी आई है।

च.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

43. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संदर्भ में यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित तौर पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में उल्लेखनीय रूप से कटौती की गई है, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करने अथवा सामान्य रूप से अन्यथा कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकने के रूप में हुआ है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर हुए प्रभाव की कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमतों को दबाने और कीमतों में गिरावट लाने, यदि कोई हो, के संदर्भ में जाँच की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत के साथ की गई है।

(क) आयात कीमत में गिरावट

44. एक याचिकाकर्ता ने जून, 2016 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया जबकि दूसरे उत्पादक का वर्ष 2013-14 तक उत्पादन नगण्य था, और वर्ष 2014-15 में उत्पादन कम था। नुकसान की अवधि के दौरान उत्पाद की आयात कीमत से यह देखा गया है कि आयात कीमत में वर्ष 2015-16 में गिरावट शुरू हुई और इसके साथ पीओआई में तेजी से गिरावट आई। अमेरिकी डॉलर में कीमत में गिरावट और अधिक तेजी से हुई। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि आयात कीमत में इस तीव्र गिरावट का एकमात्र कारण भारत में उत्पादन शुरू होना था।

| विवरण | यूओएम | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | पीओआई – ए |
|----------------------|----------------|---------|---------|---------|-----------|
| आयातों की पहुँच कीमत | रुपये/ किग्रा. | 32.65 | 33.03 | 31.18 | 24.52 |
| | सूचकांक | 100 | 101 | 96 | 75 |
| | अमेरिकी \$ | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.36 |
| | सूचकांक | 100 | 101 | 96 | 75 |

(ख) कीमत कटौती

45. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने निम्नानुसार आयातों की पहुँच कीमत की तुलना डीआई की निवल बिक्री प्राप्ति से की है। इस संबंध में व्यापार के समान स्तर पर उत्पाद की पहुँच कीमत और सभी छूटों और करों को शामिल करते हुए घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच एक तुलना की गई है। डीआई की कीमतें कारखाना स्तर पर निर्धारित की गई थीं।
46. यह देखा गया है कि पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम रही है। इस प्रकार आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

(ड.) कम कीमत पर बिक्री

47. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण डीआई को कम कीमत पर बिक्री के कारण हुए नुकसान की भी जाँच की है। इसे नीचे तालिका में देखा जा सकता है:

| विवरण | चीन | |
|-----------------------------|------------|----------------|
| | रुपये/एमटी | अमेरिकी\$/एमटी |
| क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) | *** | *** |
| पहुँच कीमत | 24,522 | 363.56 |
| कम कीमत पर बिक्री | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री(%) | *** | *** |
| कम कीमत पर बिक्री(श्रेणी %) | 40-50% | |

48. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री की वजह से काफी नुकसान हुआ है।

(घ) पाटित आयातों के कीमत दबाव एवं गिरावट प्रभाव

49. यह निर्धारित करने के लिए क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को दबा रहे हैं अथवा इनमें गिरावट ला रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को एक उल्लेखनीय हद तक दवाना अथवा अन्यथा कीमत में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है, प्राधिकारी ने नुकसान की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीओआई में जीसीएमआईएल अस्तित्व में आ गया और इस प्रकार वास्तविक लागत प्रतिनिधिक नहीं होगी, प्राधिकारी ने परियोजना रिपोर्ट से प्रेक्षित किए गए अनुसार उपर्युक्त उत्पादक द्वारा अनुमानित क्षमता उपयोग के आधार पर लागत को मानक बनाया है। इस संबंध में स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

| विवरण | यूओएम | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | पीओआई – ए |
|----------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|
| बिक्री की लागत | रुपये/किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| सूचकांक | | 100 | 103 | 106 | 108 |

| बिक्री कीमत | रुपये/किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
|----------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|
| सूचकांक | | 100 | 97 | 99 | 93 |
| आयातों की पहुँच कीमत | रुपये/किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| सूचकांक | | 100 | 101 | 96 | 75 |

50. यह देखा गया है कि नुकसान की अवधि में बिक्री की लागत बढ़ी है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। बिक्री कीमत बिक्री की लागत के स्तर से कम है। आगे यह नोट किया गया है कि पीओआई में आयातों की पहुँच कीमत में तेजी से गिरावट आई है और यह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन की लागतों के स्तर से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त जहाँ डीआई के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, वहीं इसकी बिक्री कीमत में गिरावट आई है। आयातों से घरेलू बाजार में लागत में उल्लेखनीय गिरावट और दबाव आया है।

च.3.3 घरेलू उद्योग के संबंध में आर्थिक मानदंडों की जाँच

51. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक II में यह प्रावधान है कि नुकसान के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की निष्पक्ष जाँच होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमों में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में बिक्री, लाभों, परिणाम, बाजार की हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों, पाटन के अंतर की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटकों; नकद प्रवाह, सूचियों, रोजगार, पारिश्रमिक, विकास, पूंजी निवेश को बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक घटकों और सूचकांकों का एक वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।
52. तदनुसार नीचे घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण किया गया है:

(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री

53. उत्पादन, क्षमता, क्षमता के उपयोग और बिक्री के संदर्भ में डीआई का निष्पादन निम्नानुसार है:

| विवरण | यूओएम | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | पीओआई - ए |
|--------------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| क्षमता | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| उत्पादन | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| क्षमता उपयोग | % | *** | *** | *** | *** |
| बिक्री | एमटी | *** | *** | *** | *** |

54. एक घरेलू उत्पादक अर्थात् जीसीएमआईएल द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के साथ पीओआई में घरेलू उद्योग की क्षमता बढ़ी। एक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने और एक अन्य घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादन पुनः शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप नुकसान की अवधि में उत्पादन और बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है। केमिकल्स इंडिया ने वर्ष 2013-14 से अपने उत्पादन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई और यह उल्लेख किया कि इसने चीन के पाटन के कारण इसके उत्पादन को सीमित कर दिया है। पूर्व में कंपनी घरेलू बाजार में उत्पादन तथा बिक्री कर रही थी। तथापि वर्ष 2007-08 के दौरान चीन के उत्पादकों की कीमतों में कमी के साथ उन्होंने उत्पादन में उल्लेखनीय कमी की। उसके बाद वर्ष 2013-14 में पुनः कीमत में वृद्धि के कारण कंपनी ने अपना उत्पादन पुनः शुरू कर दिया। तथापि दोनों घरेलू उत्पादकों का उत्पादन स्तर अभी भी काफी कम स्तर पर बना हुआ है। पर्याप्त माँग और नए उत्पादक द्वारा क्षमता स्थापित किए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर काम नहीं कर रहा है।

(ख) माँग में बाजार की हिस्सेदारी

55. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभावों की नीचे दिए गए अनुसार जाँच की गई है।

| विवरण | इकाई | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | पीओआई - ए |
|----------------------------------|------|---------|---------|---------|-----------|
| माँग में बाजार हिस्सेदारी | | | | | |
| डीआई की बिक्री | % | 0% | 1% | 4% | 7% |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------|------|------|------|
| अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री | % | 0% | 0% | 0% | 0% |
| संबद्ध देश से आयात | % | 100% | 99% | 96% | 93% |
| अन्य देश से आयात | % | 0% | 0% | 0% | 0% |
| कुल माँग/उपभोग | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

56. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी है जबकि संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी में थोड़ी कमी आई है। यह इस तथ्य को देखते हुए है कि मैसर्स केमिकल्स इंडिया ने वर्ष 2014-15 में उत्पादन पुनः शुरू किया और जीसीएमआईएल ने पीओआई में उत्पादन शुरू किया। यह देखा गया है कि पीओआई में बाजार में आयातों की 93% हिस्सेदारी की तुलना में घरेलू उद्योग के पास घरेलू माँग के 55% तक की आपूर्ति की क्षमता के बावजूद घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी केवल 7% है।

(ग) सूचियाँ

57. यह देखा गया है कि नुकसान की जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के औसत सूची स्तर में बढ़ोतरी हुई है। तथापि भारत में माँग और घरेलू उद्योग की बिक्री को देखते हुए घरेलू उद्योग के पास सूची स्तर अभी भी काफी कम थे। घरेलू उद्योग ने यह भी उल्लेख किया कि पीओआई के पश्चात की अवधि में घरेलू उद्योग के सूची स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग के सूची स्तर केवल उत्पादन पर रोक के कारण कम थे।

| विवरण | यूओएम | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | पीओआई - ए |
|---------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| प्रारंभ | एमटी | - | *** | *** | *** |
| समाप्ति | एमटी | - | *** | *** | *** |
| औसत | एमटी | - | *** | *** | *** |

(घ) लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह

58. लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में डीआई का निष्पादन निम्नानुसार है:

| विवरण | यूओएम | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | पीओआई - ए |
|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|-----------|
| लाभ/(हानि) | रुपये/ किग्रा. | *** | *** | *** | (***) |
| रुझान | | 100 | 31 | 19 | (69) |
| लाभ/(हानि) | लाख रुपये | *** | *** | *** | (***) |
| रुझान | | 100 | 2687.5 | 9225 | (53962) |
| नकद लाभ | लाख रुपये | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | | 100 | 2411 | 8833 | 237466 |
| लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल | % | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | | 100 | 2350 | 4867 | 8.33 |

59. इस तथ्य को देखते हुए कि जीसीएमआईएल पीओआई में अस्तित्व में आई और इस प्रकार वास्तविक लागत प्रतिनिधिक नहीं होगी, प्राधिकारी ने परियोजना रिपोर्ट से प्रेक्षण किए गए अनुसार उपर्युक्त उत्पादक द्वारा अनुमानित क्षमता उपयोग के आधार पर लागत को मानक बनाया है।

60. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की लाभकारिता में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को पीओआई में अत्यधिक नुकसान हो रहा है। नुकसान की अवधि में नकद प्रवाह में सुधार हुआ है। निवेश की गई पूंजी पर प्रतिफल कम था और पीओआई में कुछ हद तक सकारात्मक बना हुआ है। निवेश की गई पूंजी पर प्रतिफल वर्ष 2015-16 में बढ़ने के बाद एक बार पुनः पीओआई में कम हो गया।

(ङ.) उत्पादकता

61. यह देखा गया है कि नुकसान की अवधि में प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता के संदर्भ में उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जो उत्पादन की गति के अनुरूप है। तथापि उत्पादकता में सुधार के बावजूद लाभकारिता में गिरावट आई।

| उत्पादकता | यूओएम | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | पीओआई - ए |
|----------------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| प्रति कर्मचारी | संख्या | *** | *** | *** | *** |
| प्रति दिन | संख्या | *** | *** | *** | *** |

(ख) रोजगार और पारिश्रमिक

62. यह देखा गया है कि तृकसान की जाँच अवधि में डीआई के पास रोजगार और भूगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है।

| विवरण | यूओएम | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | पीओआई |
|------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| रोजगार | संख्या | *** | *** | *** | *** |
| पारिश्रमिक | लाख रुपये | *** | *** | *** | *** |

(छ) वृद्धि

63. जीसीएमआईएल द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने को देखते हुए मात्रा के मानदंडों पर घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही है, जबकि कीमत के मानदंडों पर वृद्धि नकारात्मक रही है। तथापि मात्रा के मानदंडों पर वृद्धि भी भारत में सृजित क्षमताओं, उत्पाद की माँग और पूर्व में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की गई उपयोग क्षमता को देखते हुए की जा सकने वाली वृद्धि से बहुत कम थी।

| वृद्धि | यूओएम | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | पीओआई – ए |
|------------------------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| उत्पादन | % | - | 8,715 | 406 | 78 |
| क्षमता उपयोग | % | - | 4 | 15 | (5) |
| घरेलू बिक्री की मात्रा | % | - | 8,698 | 407 | 76 |
| प्रति इकाई बिक्री कीमत | % | - | -3.02 | 2.23 | -6.23 |
| प्रति इकाई पीबीटी | % | - | -69.17 | -32.45 | -432.62 |
| आरओसीई | % | - | 2268 | 107 | -100 |

(ज) पूंजीगत निवेश बढ़ाने की क्षमता

64. प्राधिकारी ने यह देखा कि डीआई ने हाल ही में निवेश किए थे जो अत्यधिक खराब प्रदर्शन कर रहे हैं।

(झ) पाटन का स्तर और पाटन का अंतर

65. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर आ रहे हैं और पाटन का अंतर उल्लेखनीय है।

(ग) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

66. जाँच में यह पता चला है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की अच्छी माँग है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत, बिक्री की लागत और बिक्री कीमत से कम है। यह भी नोट किया गया है कि दूसरे देशों से आयात लगभग न के बराबर हैं। इस प्रकार घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक मुख्य रूप से आयात कीमतें हैं।

(ट) नुकसान की मात्रा और नुकसान का अंतर

67. पीओआई के दौरान नुकसान के अंतर का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक III के अनुसार निर्धारित डीआई द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयात के पहुँच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार निकाला गया नुकसान का अंतर निम्नानुसार है:

नुकसान के अंतर की तालिका

| विवरण | मैसर्स मोंगोलिया रिशेंग रिसाइकलिंग आरसीएल | | चालको जिबो इन्टरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि. | | चालको किंगडाओ इन्टरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि. | | अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक | |
|----------------------------|--|------------|--|----------------|---|----------------|------------------------------|----------------|
| | रुपये/एमटी | अमेरिकी \$ | रुपये/एम टी | अमेरि की \$ | रुपये/एम टी | अमेरि की \$ | रुपये/एम टी | अमेरि की \$ |
| क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| पहुँच कीमत | 24,582.83 | 364.46 | 24,471.66 | 362.81 | 24,360.73 | 364.52 | 21,631.05 | 320.70 |
| नुकसान का अंतर | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| नुकसान का अंतर (%) | *** | | *** | | *** | | *** | |
| नुकसान का अंतर (श्रेणी %) | 40-50% | | 40-50% | | 40-50% | | 60-70% | |

(ठ) अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

68. डीआई की कीमतों में कटौती और कीमतों को दबाने तथा गिरावट लाने के प्रभावों के संदर्भ में लगातार नुकसान, पाटित आयातों के घरेलू उद्योग की कीमतों पर मात्रा और कीमत प्रभावों के अस्तित्व की जाँच करने के बाद यह देखने के लिए कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त किसी अन्य कारक का घरेलू उद्योग को हुए नुकसान में कोई योगदान हो सकता है, प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार पाटनरोधी शुल्क के संबंध में भारतीय नियमों और समझौते के तहत सूचीबद्ध अन्य सूचक मानदंडों की जाँच की गई है।

i) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

69. यह देखा गया है कि दूसरे देशों से आयात लगभग न के बराबर हैं और इसलिए वे डीआई को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं।

ii) मांग में संकुचन

70. नुकसान की पूर्ण जांचाधीन अवधि में मांग में वृद्धि हुई है और इस प्रकार इससे घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हो सकता।

iii) उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन

71. पीयूसी के संदर्भ में उपभोग के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए उपभोग की पद्धति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान पहुंचाने की संभावना नहीं हो सकती।

iv) प्रौद्योगिकी में विकास

72. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाला एक कारक नहीं माना जा सकता।

v) प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधी पद्धतियाँ

73. कोई व्यापार प्रतिबंधी पद्धति लागू नहीं है।

vi) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

74. यथासंभव सीमा तक घरेलू निष्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन और इस संबंध में नुकसान की जाँच की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा नुकसान की पूरी जांचाधीन अवधि के दौरान कोई निर्यात बिक्री नहीं की गई और इसलिए इसे घरेलू उद्योग को नुकसान का एक संभावित कारण नहीं माना जा सकता।

(vii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन

75. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे तथा बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन ने प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में किए गए आकलन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा जिस सूचना पर विचार किया गया है वह केवल विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में है।

(viii) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

76. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन जैसा ही रुझान है और इसमें वृद्धि देखी गई है। उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने का एक कारण नहीं है।

छ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

77. प्राधिकारी ने प्रयोक्ता उद्योग और आयातकों द्वारा व्यक्त चिंताओं को नोट किया है। सामान्य रूप में पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है, इस स्थिति को देखते हुए प्राधिकारी

महसूस करते हैं कि विनिर्माताओं; निर्यातकों; आयातकों और प्रयोक्ताओं के लिए संतुलित एवं समतुल्य वातावरण बनाना सभी के हित में है।

ज. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ज.1 घरेलू उद्योग के विचार

78. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. केमिकल्स इंडिया एक नया उत्पादक नहीं है और 1992 में उत्पादन शुरू किया था। अनुचित रूप से कीमतों पर आयातों से अंततः कंपनी को 2008-09 में उत्पादन रोकना पड़ा। कीमतों के सामान्यीकरण पर इसने उत्पादन पुनः शुरू किया क्योंकि इसने लागतों में वृद्धि के बावजूद कम कीमतों पर बड़े हुए संबद्ध देश से आयातों की मात्रा का उत्पादन बढ़ाया।
- ii. जीसीएमआईएल राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य में खनिज विकास के प्रयोजन के लिए स्थापित एक सार्वजनिक लिमिटेड उद्यम के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह संयंत्र विकासाधीन स्थिति में स्थापित किया गया था और यह क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए है। उत्पादन 2016 में शुरू हुआ, परंतु इससे संबद्ध आयातों की कीमतें कम हो गईं जिससे उसे उत्पादन आरंभ करने के वर्ष में ही अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- iii. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार न होने के कारण यह सही नोट किया गया है कि चीन को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार नहीं दिया जा सकता और महत्वपूर्ण सूचना, यथा उनके संबंधित पक्षकारों के नाम, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके संबंधित पक्षकार के ब्यौरे प्रकट करने में विफलता, उनके द्वारा प्राप्त लाभों और प्रोत्साहनों के संबंध में तथ्यों को छिपाने के कारण उत्तर को रद्द किया जाना चाहिए। संबद्ध सामानों के उत्पादन और बिक्री में शामिल निर्यातकों के संबंधित पक्षकारों ने भी भाग नहीं लिया है।
- iv. दो विभिन्न चैनलों के नाम पर दो पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन रेंज अवार्ड करना कम शुल्क लगाने के लिए उत्पादक को अनुचित, अप्रत्याशित प्रोत्साहन देता है। सामान्य उत्पादक के लिए पाटनरोधी शुल्क समाप्त होना चाहिए और प्रत्येक उत्पादक के लिए एक विशिष्ट शुल्क तथा प्रत्येक निर्यातक के लिए एक विशिष्ट शुल्क होना चाहिए।
- v. पूरी क्षति जांच अवधि में मांग में वृद्धि के बावजूद बाजार का अधिकतर हिस्सा घरेलू उद्योग की पर्याप्त क्षमता होने पर भी संबद्ध आयातों द्वारा रखा जाता है।
- vi. आयात मात्रा पूरी दृष्टि से बढ़ी है जबकि उसकी तुलना में उत्पादन और जीसीएमआईएल द्वारा उत्पादन शुरू करने के कारण खपत में गिरावट आई है और केमिकल्स इंडिया द्वारा व्यापार पुनः शुरू करने से सापेक्ष रूप से भारतीय उत्पादन का 1336 प्रतिशत और भारतीय खपत का 93 प्रतिशत रहता है।
- vii. पहुँच कीमत में 2014-15 से गिरावट आई है और जांच की अवधि में उसने काफी गिरावट दर्शाई। गिरती हुई कीमतें जीसीएमआईएल द्वारा व्यापार शुरू करने और केमिकल्स इंडिया द्वारा पुनः व्यापार शुरू करने के परिणामस्वरूप हैं। इस अवधि के दौरान कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि हुई। प्राधिकारी द्वारा माने गए मानक आंकड़े भी क्षति दर्शाते हैं।
- viii. जीसीएमआईएल का संयंत्र जांच की अवधि में प्रचालनात्मक था जो क्षमता में वृद्धि दर्शाता है, परिणामस्वरूप बढ़ा हुआ उत्पादन और बिक्री दर्शाता है। बड़े हुए उत्पादन और बिक्री के बावजूद घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन उचित रूप से कम स्तरों पर है।
- ix. यहां तक कि जब इष्टतम उत्पादन माना जाए तो आसन्न संचित मालसूची बनी होती तथा इष्टतम उत्पादन पर क्षति रहित कीमत के प्रयोजन के लिए भी विचार नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अन्य प्रयोजनों के लिए भी विचार किया जाना चाहिए। मालसूची में जांच की अवधि के बाद की अवधि में और गिरावट आई है।
- x. मानक लागतों से भी लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानियां हो रही हैं तथा मुश्किल से ही सकारात्मक आरओसीई है।
- xi. व्यक्त पांच वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क निर्धारित स्वरूप में अमेरिकी डॉलर/मी. टन में लगाए जाने की आवश्यकता है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

79. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. प्राधिकारी ने चालकों तथा अन्य उत्तरदाता पक्षकारों द्वारा निर्यातित सामानों की पहुँच कीमतें प्रकट की हैं, परंतु घरेलू उद्योग की कुल क्षति रहित कीमत तथा मालसूची, मजदूरी, उत्पादकता, क्षमता, उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग जैसे विभिन्न आर्थिक मानदंडों के अगोपनीय रूपांतर न तो सूचीबद्ध रूप में और न ही प्रतिशत रूप में प्रकट किए हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे सूचीबद्ध रूप में घरेलू उद्योग के सभी आर्थिक मानदंडों को इस तरह से प्रकट करें कि उनसे उत्तरदाताओं की सार्थक टिप्पणियां करने में क्षमता बाधित न हो।
- ii. गैर-प्रतिभागी उत्पादकों के लिए पहुँच मूल्य तथा परवर्ती क्षति मार्जिन डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए, तथापि, प्राधिकारी ने उत्तरदाता निर्यातकों की कीमत पर विचार किया है।
- iii. यह गलत निर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता ही देश में संबद्ध सामानों के उत्पादक हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम से प्राप्त सूचना के अनुसार और उसकी कारपोरेट प्रस्तुतियों से यह दर्शाया गया है कि नालको डिटर्जेंट ग्रेड के जियोलाइट के उत्पादन में लगा हुआ है। चूंकि, प्राधिकारी को अन्य मंत्रालयों से सूचना मंगाने का अधिकार प्राप्त है, अतः वह खान मंत्रालय से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भी किया जाए।
- iv. नालको को अन्य भारतीय उत्पादकों में कुछ लाभ हैं, यथा – कच्ची सामग्री का लाभ, एल्युमिना और जियोलाइट 4ए उत्पादन के लिए वही सुविधा, अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं से तुलना करके नालको द्वारा उत्पादन लागत कम है। यह जांच की जानी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ताओं को क्षति अप्रयोज्य प्रक्रिया तथा नालको के साथ प्रतिस्पर्द्धा के कारण है।
- v. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उस सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया है, जैसा कि *शेनयांग मस्तुशिता एस. बैट्री कं. लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्री लि.* में निर्धारित है। प्राधिकारी की घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने की परिपाटी अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा अपनाई गई परिपाटी के अनुरूप नहीं है।
- vi. चूंकि, जीसीएमआईएल ने ही जांच की अवधि में उत्पादन शुरू किया, अतः वह वास्तविक मंदी का दावा ही कर सकता है, न कि वास्तविक क्षति का। चूंकि, यह एक नया उत्पादक है, अतः प्राधिकारी को जीसीएमआईएल के आंकड़ों को अलग करने के बाद ही एनआईपी निर्धारित करना चाहिए। वितीय लागतें और अन्य ऐसी लागतें केवल उत्पादन शुरू करने के कारण ही बढ़ी हैं। इस संबंध में, एसबीआर के मामले में जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम का संदर्भ दिया जाता है जिसमें एनआईपी का निर्धारण स्थापित उत्पादक के ही आंकड़ों के आधार पर किया गया था।
- vii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों का मूल्यांकन विरोधाभासी तरीके से किया है क्योंकि एक स्थान पर यह नोट किया गया है कि केमिकल्स इंडिया ने 2014-15 में उत्पादन शुरू किया और यह कि जीसीएमआईएल ने जांच की अवधि में उत्पादन शुरू किया, जबकि दूसरे स्थान पर यह नोट किया गया है कि केमिकल्स इंडिया ने 2013-14 से उत्पादन के संबंध में सूचना दी। जांच की अवधि में आधार वर्ष कम उत्पादन मात्रा के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता।
- viii. कीमत कटौती की जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए गई है, परंतु प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार उसकी जांच पूरी क्षति जांच अवधि के लिए की जानी है। जहां तक घरेलू उद्योग का जांच की अवधि में लागत में वृद्धि के संबंध में दावे का संबंध है, इन्पुट सोडा ऐश और बाक्साइट की कीमत इस दावा की गई कीमत वृद्धि को नहीं दर्शाती।
- ix. अध्याय 38 और 28 के अंतर्गत विभिन्न कोडों को शामिल करके विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बढ़ाने की मांग कोई पर्याप्त साक्ष्य दिए बिना की गई है।
- x. याचिकाकर्ताओं ने अपने लिखित अनुरोधों में यह कहा है कि विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत आता है। संबद्ध सामान याचिका दायर करते समय सीमा शुल्क उप शीर्ष 38249022 के अंतर्गत वर्गीकृत थे; परंतु उन पर वर्गीकरण को 38249922 में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, लेन-देन वार आयातों का पृथक्करण यह दर्शाता है कि संबद्ध सामान विभिन्न कोडों के तहत आयात किए जा रहे हैं। यह जांच विचाराधीन उत्पाद विशिष्ट है न कि एचएस कोड विशिष्ट। एचएस कोड केवल संकेतात्मक हैं और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- xi. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे स्पष्ट करें कि घरेलू उद्योग की लागतों का मानक बनाते समय किन-किन कारकों पर विचार किया गया है और अगोपनीय आधार पर परिकलन को प्रकट करें।
- xii. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों का परिकलन सहयोगी निर्यातकों और उत्पादकों द्वारा दायर सूचना के आधार पर किया जाए। प्राधिकारी से अनुरोध है कि उत्पादन लागत, एसजीए आदि के लिए माने गए सूचीबद्ध आंकड़ों/रैंजों को प्रकट करें।

- xiii. बाजार हिस्से का विश्लेषण अथवा इन कारकों में वृद्धि अथवा कमी के बजाए अन्यथा क्षमता उपयोग अनुबंध-II के अनुसार किया जाना अनिवार्य नहीं है। बाजार हिस्सा और क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि में काफी सुधार हुआ है। क्षमता के पर्याप्त उपयोग का विश्लेषण संगत नहीं है और इन मानदंडों के लिए कोई क्षति रिकार्ड नहीं किया जा सकती। चूंकि, उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्से में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक काफी वृद्धि हुई है, अतः इन कारकों के आधार पर क्षति रिकार्ड नहीं की जा सकती।
- xiv. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री क्षति के कारक नहीं हैं, जैसा कि *ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2011 (270) ई.एल.टी. 696 (ट्राई-डेल.)* के मामले में माननीय सेसटेट द्वारा निर्धारित किया गया है।
- xv. घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि के लिए कोई कारण अथवा विश्लेषण रिकार्ड नहीं किया गया है। यह केवल उनकी अदक्षता और हानियों के कारण बड़ी है। इसका कोई विश्लेषण नहीं है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन संबद्ध आयातों के बावजूद कैसे सुधरा।
- xvi. औसत मालसूची के आधार पर मालसूची का विश्लेषण गलत है क्योंकि इसे बिक्री/उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में अंत मालसूची के आधार पर किया जाना चाहिए। यह दर्शाएगा कि घरेलू उद्योग की मालसूची क्षति की अवधि में काफी कम हुई है।
- xvii. रिशेंग गर्कविन ग्रुप और अन्य निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन के बीच काफी अंतर है। उसके लिए क्षति मार्जिन में काफी अंतर होना चाहिए क्योंकि रिशेंग गर्कविन ग्रुप की कीमतें अन्य निर्यातकों की कीमतों से अधिक हैं। अनुरोध है कि इसकी पुनः जांच की जाए।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

80. संबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। उनमें उठाए गए मुद्दों को जांच के दौरान पूर्व में पहले ही उठा दिया गया है और उनकी समुचित रूप से समाधान भी किया गया है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की स्पष्टता के लिए उनकी निम्नलिखित के रूप में जांच की जा रही है:
- जहां तक आंकड़ों को प्रकट करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय सूचना को सार्वजनिक दस्तावेज में प्रकट नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी ने पूर्व में जारी प्रकटन विवरण में और वर्तमान जांच परिणाम में व्यवहार्य सीमा तक सूचना का अगोपनीय रूपांतर पहले ही प्रकट कर दिया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने पहले ही विस्तृत विश्लेषण दे दिया है जिससे भी हितबद्ध पक्षकार गोपनीय आधार पर दी गई और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सूचना के सार को भी समझ सकते हैं।
 - जहां तक गैर-उत्तरदायी निर्यातकों के लिए मार्जिन का संबंध है, वह नियम 6(8) के अनुसार और प्राधिकारी की विगत परिपाटी के अनुसार निर्धारित किया गया है। असहयोगी निर्यातक के संबंध में प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों का मूल्यांकन करने और निर्यातकों की प्रश्नावलियों के उत्तरों का मूल्यांकन करने के बाद आयात कीमत पर विचार कर सकते हैं। वस्तुतः यह पाया गया है कि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े वास्तव में कम कीमत पर आयात दर्शाते हैं।
 - जहां तक नालको द्वारा उत्पादन का संबंध है, प्राधिकारी इस बात को दोहराते हैं कि जांच यह दर्शाती है कि नालको ने जांच की अवधि के दौरान उस उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है। कंपनी ने प्राधिकारी को इस बात की पुष्टि की है कि नालको द्वारा जियोलाइट 4ए स्वरूप का उत्पादन दिसंबर, 2013 के प्रथम सप्ताह से रोक दिया गया था। कंपनी ने दावा किया है कि उसका उत्पादन मुख्य रूप से कम विपणनीयता के कारण रोका गया था क्योंकि दूसरे देशों से आपूर्ति किए गए खनिज जियोलाइट उनके जियोलाइट से काफी सस्ते थे। यद्यपि, कंपनी द्वारा उल्लिखित कारण प्राधिकारी द्वारा अलग से सत्यापित नहीं किया गया था, फिर भी नालको ने इस मामले की जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है।
 - जहां तक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश पर विचार करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का सुझाव नहीं दिया है, जिस पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा सके। यद्यपि, याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि इस संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं थी, तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने भी कोई उपयोगी सूचना नहीं दी। अतः प्राधिकारी "अन्य कोई उपयुक्त आधार" अर्थात् कानून द्वारा अनुमत सामान्य मूल्य का निर्माण का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं।
 - जहां तक क्षति और क्षति मार्जिन निर्धारण के प्रयोजन के लिए जीसीएमआईएल को शामिल करने से संबंधित तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णय इस निमित्त पूर्व निर्धारणों के अनुरूप है। जीसीएमआईएल ने जुलाई, 2016 माह से जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का उत्पादन और बिक्री वाणिज्यिक रूप से शुरू कर दी है और 15 माह (अप्रैल,

- 2016 – जून, 2017) में से जांच की अवधि के 12 माह के लिए वाणिज्यिक रूप से प्रचालन में थी। एसबीआर मामले में रिलायंस ने जांच की अवधि के बाद में ही वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया था। जहां तक कंपनी की संभावित उच्चतर लागत का संबंध है, एनआईपी का निर्धारण जीसीएमआईएल द्वारा उत्पादन शुरू करने के कारण मानक लागत पर विचार करते हुए किया गया है।
- vi. यह स्पष्ट किया जाता है कि केमिकल्स इंडिया का 2013-14 में नगण्य उत्पादन था और 2014-15 में कम उत्पादन था। आधार वर्ष में क्षति जांच के लिए अलग नहीं किया गया है। तथापि, आधार वर्ष में कम उत्पादन के कारण केमिकल्स इंडिया के लिए लागत को उचित रूप से मानक बनाया गया है तथा जीसीएमआईएल की लागत कंपनी द्वारा उत्पादन शुरू करने के कारण जांच की अवधि के लिए मानक बनाई गई है।
- vii. जहां तक क्षति की अवधि के लिए कीमत कटौती का निर्धारण करने के संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून में जांच की अवधि में कीमत कटौती का विश्लेषण करने की अपेक्षा है। कानून में पूरी क्षति अवधि में कीमत कटौती का निर्धारण करने की अपेक्षा नहीं है। यद्यपि, आयातों में वृद्धि और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास क्षति की अवधि में निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, तथापि, पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन जांच की अवधि के लिए ही निर्धारित किए गए हैं।
- viii. जहां तक सीमा शुल्क वर्गीकरण शामिल करने का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने लिखित अनुरोधों में यह कहा था कि विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत आता है। संबद्ध सामान याचिका दायर करते समय सीमा शुल्क उप शीर्ष 38249022 के अंतर्गत वर्गीकृत थे; परंतु उन पर वर्गीकरण को 38249922 में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, लेन-देन वार आयातों का पृथक्करण यह दर्शाता है कि संबद्ध सामान विभिन्न कोडों के तहत आयात किए जा रहे हैं। यह जांच विचाराधीन उत्पाद विशिष्ट है न कि एचएस कोड विशिष्ट। एचएस कोड केवल संकेतात्मक हैं और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि जांच का एक प्रयोजन पाटनरोधी शुल्क के लिए लागू जिम्मेदार वस्तु तथा उसके सीमा शुल्क वर्गीकरण की पहचान करना है।
- ix. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तथ्य के आधार पर कि एक याचिकाकर्ता कंपनी ने जांच की अवधि में उत्पादन शुरू किया, जबकि दूसरी ने क्षति जांच अवधि के आधार वर्ष में पुनः उत्पादन शुरू किया और घरेलू उद्योग में पाटित उत्पादों के प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की लागतों को उचित रूप से मानक बनाया गया है। एक नई कंपनी होने के नाते और पूर्व वर्षों के कोई आंकड़े न होने के कारण जीसीएमआईएल की लागतें परियोजना शुरू करने से पूर्व माने गए अनुमान के आधार पर ली गई हैं जिसमें क्षमता के 70 प्रतिशत उपयोग का इष्टतम लक्ष्य देश में उत्पाद की मांग को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था।
- x. जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों का संबंध है कि परियोजना रिपोर्टें केवल अवधारणाएं हैं और सही तस्वीर नहीं दर्शाते, प्राधिकारी मानते हैं कि जबकि इतनी मात्रा की लागत और निवेश व्यापार में शामिल है तो बाजार अनुसंधान और आसूचना के बाद तथा व्यवहार्यता और अर्थक्षमता अध्ययनों के आधार पर उत्पाद की अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के बाद कंपनी कार्य करती है। इन व्यवहार्यता और अर्थक्षमता अध्ययनों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में यह सिद्ध नहीं किया गया है कि ये व्यवहार्यता और अर्थक्षमता अध्ययन वर्तमान मामले में अवास्तविक हैं।
- xi. जहां तक केमिकल्स इंडिया के लिए लागतों के लिए मानक बनाने का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि लागतें 2015-16 में प्राप्त उपयोग स्तरों पर विचार करते हुए तथा उन्हें इष्टतम स्तरों पर होना मानते हुए मानक बनाई गई हैं।
- xii. जहां तक घरेलू उद्योग की लागतों में वृद्धि का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि इस अवधि में नई सामग्री की लागत बढ़ी हैं और घरेलू उद्योग पर अदक्षताओं का कोई साक्ष्य नहीं है।
- xiii. अलग से अंत और आदि की मालसूची पर विचार कर मालसूची का विश्लेषण यह दर्शाता है कि अंत मालसूची वस्तुतः आदि मालसूची से अधिक हैं।
- xiv. उत्तरदाता निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की इनकी रेंज के संदर्भ में उसमें तथाकथित अंतर के लिए पुनः जांच की गई है। वह इन जांच परिणामों में सही-सही दर्शाई गई है।

झ. सिफारिश

81. प्राधिकारी उपर्युक्त पर विचार करते हुए यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा सभी निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं पर

सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। जांच शुरू करने पर और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, पाटन, क्षति तथा उसके कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच करने पर और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति सिद्ध होने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को रोकने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी निम्नलिखित रूप में वर्णित स्वरूप एवं तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।

82. मामले की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए शुल्क ढांचे के संबंध में अमेरिकी डॉलर के रूप में पाटनरोधी शुल्क के निर्धारित स्वरूप की सिफारिश करना उपयुक्त माना जाता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति का समाधान करने के लिए पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन से कम के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, निम्नलिखित तालिका के कॉलम 7. में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

| क्रम सं. | शीर्ष/उप-शीर्ष* | वस्तुओं का विवरण | मूल या निर्यातक देश | उत्पादक | निर्यातक | शुल्क राशि (अमेरिकी डॉलर/मी. टन) |
|----------|--|-------------------------------|---------------------|---|--|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 38249922 38249090 38249990 28429090 28269000 28399090 28421000 | जियोलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड) | चीन जन. गण. | इनर मंगोलिया रिशेंग रिसाइकिलिंग रिसोर्स कं. लि. (आईएमआरआरआरसीएल) | तियानजिन गर्कविन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि. (टीजीआईटीसीए) | 163.96 |
| 2 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चालको शानडोंग एडवांस मैटेरियल कं. लि. (सीएसएएमसीएल) | चालको जिबो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि. (सीजेडआईटीसीएल); | 165.61 |
| 3 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चालको शानडोंग एडवांस मैटेरियल कं. लि. (सीएसएएमसीएल) | चालको किंगदाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि. (सीक्यूआईटीसीएल) | 163.90 |
| 4 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | उपरोक्त क्रम सं. 1 से 3 को छोड़कर कोई अन्य | | 207.72 |

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। उपर्युक्त विचाराधीन उत्पाद किसी अन्य एचएस कोड के तहत आयातित किए जाने पर भी उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन होना चाहिए।

83. ऊपर सिफारिश की गई शुल्क दरें उसमें उल्लिखित विनिर्दिष्ट उत्पादक एवं निर्यातक द्वारा निर्यातों के लिए लागू हैं। सीमा शुल्क प्राधिकारियों को संबद्ध सामानों की मंजूरी के समय उत्पादक का नाम सत्यापित करना चाहिए। अधिसूचित निर्यातक के नाम के परिवर्तन के लिए अनुरोध, प्राधिकारि द्वारा 17 सितंबर 2018 के व्यापार नोटिस संख्या 12/2018 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

84. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुँच मूल्य मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा, जैसा कि सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित किया गया है तथा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।
85. इस अंतिम जांच परिणाम के कारण उत्पन्न होने वाली केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2018

FINAL FINDING

[Case No. O.I. 25/2017]

Subject: Antidumping investigation concerning imports of Zeolite 4A (Detergent grade) originating in or exported from People's Republic of China.

F.No.6/14/2017-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof; the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) had initiated an Antidumping investigation against imports of Zeolite 4A (Detergent Grade) originating in or exported from People's Republic of China vide Notification No. 06/14/2017-DGAD on 2nd January, 2018.

1. And whereas, M/s Gujarat Credo Mineral Industries Ltd and M/s Chemicals India (hereinafter also referred to as "Petitioners" or "Applicants") filed an application in the present case before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules for initiation of Antidumping investigation concerning imports of Zeolite 4A (Detergent grade) (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter also referred to as the subject country) and requested for imposition of Antidumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
2. And Whereas, the Authority on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant to justify initiation of Antidumping investigation issued a public notice vide Notification No. 6/14/2017-DGAD on 2nd January, 2018 to examine and determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the DI.

A. PROCEDURE

3. Procedure described herein below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:
 - i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the Antidumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 *supra*.
 - ii. The Authority sent a copy of the Initiation Notification to the concerned Embassy of the subject country in India; known producers/exporters from the subject country; known importers/users in India; other Indian producers and the DI as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the Initiation Notification.

- iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- iv. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- v. The Authority sent Exporter's Questionnaire and Supplementary Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. M/s Chalco Qingdao International Trading
 - b. M/s Chalco Zibo International Trading Co.
 - c. M/s Xiamen Zhongzhao Imp and Exp Co Ltd
 - d. M/s Tianjin Gerkwin International Trading Company Ltd
 - e. M/s Guangzhou Chemicals Imp. & Export Co Ltd
 - f. M/s Huiying Chemical Industry
- vi. In response to the above notification, the following exporters/producers responded and submitted questionnaire responses.
 - a. M/s Inner Mongolia Risheng Recycling Resource Co., Ltd.
 - b. M/s Tianjin Gerkwin International Trading Co., Ltd.
 - c. M/s Chalco Shandong Advanced Material Co., Ltd
 - d. M/s Chalco Qingdao International Trading Co., Ltd.
 - e. M/s Chalco Zibo International Trading Co., Ltd
- vii. Legal submissions were also filed by Chalco Shandong Advanced Material Co., Ltd, Chalco Qingdao International Trading Co., Ltd., Chalco Zibo International Trading Co., Ltd, Tianjin Gerkwin International Trading Co, Xiamen Zhongzhao Import and Export Co. Ltd and China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters
- viii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users/user associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. M/s Nirmesh Enterprises Private Limited
 - b. M/s Pee Cee Cosma Sope Limited
 - c. M/s Zeolites and Allied Products Private Limited
 - d. M/s Ankush Enterprises
 - e. M/s Sankur Exim Pvt. Ltd.
 - f. M/s Vimal Agencies
 - g. M/s Vaghani Inc.
 - h. M/s S.B. International
 - i. M/s Shree Soaps & Chemical Industries
 - j. M/s Plasma Exim Llp
 - k. M/s Nirma Limited
 - l. M/s Devanshi Exports Private Limited
 - m. M/s Oasis Capital Private Limited
 - n. M/s Dev Overseas
 - o. M/s Rspl Limited (Ghari Detergent)
 - p. M/s Procter & Gamble Home Products Private Limited
 - q. M/s Balleshwar Exim Private Limited
 - r. M/s Agarwal Minerals
 - s. M/s Aaditya Finechem Pvt.Ltd.
- ix. The following importers of the subject goods responded by filing questionnaire responses
 - a. M/s Aaditya Finechem (P) Ltd.
 - b. M/s Hindustan Unilever Limited
- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

- xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- xii. The Non-Injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the DI on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Antidumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Antidumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the DI.
- xiii. The Authority held a public hearing on 25th May, 2018 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6), which was attended by the representatives of DI and other interested parties. All the parties who presented their views in the public hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and to submit their rejoinders thereon.
- xiv. The verification of the information provided by the DI was carried out to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.
- xv. The petitioners had proposed the period April 2016 – March 2017 (12 Months) as the period of investigation in the petition. For enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority determined the POI as April 2016 to June 2017 (15 Months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods April 2013-March 2014, April 2014-March 2015, April 2015-March 2016 and the POI.
- xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority in this notification.
- xvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- xix. ‘***’ in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as **₹ 67.45 = US\$1**.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

B.1 Views of the Domestic Industry

4. The views of the DI are as follows:
 - i. The product under consideration (PUC) is “Zeolite 4A (Detergent Grade)” also known as “Synthetic Zeolite 4A”. Zeolites are micro porous crystalline solids with well-defined structures. Generally, they contain silicon, aluminium and oxygen in their framework and cat-ions, water and/or other molecules within their pores. Many occur naturally as minerals, and are extensively mined in many parts of the world. Others are synthetic, and are made commercially for specific uses in various industries. The general formula of Zeolite is given as $\text{Na}_x[(\text{AlO}_2)_x(\text{SiO}_2)_y] \cdot z\text{H}_2\text{O}$.
 - ii. Due to cubical shape with rounded corners and edges, Zeolite 4A crystals do not remain on fabrics and are easily removed on rinsing. They have high sequestering power even at high temperatures and Alkali reaction with pH less than 12. The average particle size is less than 5micron. This makes it suitable to pass through the mesh size of clothes and preventing greying thereby. The subject good are mainly used as a builder in detergents
 - iii. Detergent grade zeolites are primarily water softener compounds, used to remove calcium and magnesium ions

from hard water. This results in softening of water, which requires less soap for the same cleaning effort, as soap is not wasted mopping up calcium ions.

- iv. PUC falls under Chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975. The subject goods were classified under customs sub-heading 38249022 at the time of filing of petition; but the classification has thereupon changed to 38249922. It is pertinent to note that the customs classification indicated is only indicative. The PUC has been imported under different heads such as - 38249090, 38249990, 28429090, 28269000, 28399090 & 28421000.
- v. Since the PUC is being imported under various codes, the Authority may kindly specify these indicative codes as well in the duty table. Only the duty table contents are relevant in this regard. Anything mentioned in the para relating to "product under consideration" but not stated in duty table is likely to get ignored while issuing notification by the Ministry of Finance. Customs authorities at the port consider and rely upon the notifications notification issued by the MOF. Hence it is of utmost important that the duty table itself include all these clarifications.
- vi. A large number of imports are taking place under such codes despite the existence of a dedicated code. The possibility of circumvention becomes very high if relevant codes are not mentioned in customs notification.
- vii. GCMIL produces Zeolite 4A for detergent industry use and supplies to all major detergent makers in India, including Nirma, Ghari, Jyothy Lab and P&G on regular basis. GCMIL product matches with all other producers including Chinese. Attachment related to the Exhibits displaying communication between HUL and GCMIL regarding quality being unacceptable, has not been shown to the petitioner, claiming confidentiality. GCMIL has not received any technical data from HUL concerning the results of the sample submitted as claimed by HUL and only false claims in this regard have been raised.
- viii. Difference in quality is not a sufficient justification for exclusion of a product reference has been laid on the decision of the Hon'ble CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited Versus DA.

B.2 Views of Interested Parties

5. The views of other interested parties are as follows:
 - i. The product scope includes products not being commercially produced and manufactured by the Petitioners. Therefore, the imported product and the DI's product cannot be considered as "like articles".
 - ii. Petitioners are unable to manufacture and commercially supply Zeolite Grade 4A as per the technical specifications required by HUL. Hence it is requested to exclude Zeolite Grade 4A specifications which matches the bulk density and the content as provided in HUL's specifications.

B.3 Examination by the Authority

6. The PUC is Synthetic Zeolite 4A (Detergent Grade). Zeolites are micro porous crystalline solids with well-defined structures. Generally, they contain silicon, aluminum and oxygen in their framework and cat-ions, water and/or other molecules within their pores. They also occur naturally as minerals, and are extensively mined in many parts of the world. Others are synthetic, and are made commercially for specific uses in various industries. The general formula is given as $\text{Na}_x[(\text{AlO}_2)_x(\text{SiO}_2)_y] \cdot z\text{H}_2\text{O}$.
7. The PUC functions as a detergent builder primarily as a water softener resulting in softening of water, which requires less soap for the same cleaning effort, as soap is not wasted mopping up calcium ions.
8. The Authority notes that the PUC falls under Chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975. The subject goods were classified under customs sub-heading 38249022 at the time of filing of petition; however, the classification has thereupon changed to 38249922. It is further noted that the product is also being imported under different headings such as – 38249090, 38249990, 28429090, 28269000, 28399090 & 28421000. In view of the same, all such reported headings are also included in the scope of the present investigation. In any case, the Customs classification indicated is only indicative.
9. As regards the claims of HUL that the product produced by the DI is unfit for the desired use, the Authority notes that HUL was specifically directed to provide evidence in support of its claim. While no verifiable evidence was provided by the company, the DI provided documents showing that HUL has not established how the goods produced by the two petitioner companies cannot be used by them. In view of the same and after considering the

evidence placed on record by DI, the Authority proposes to hold that there is no known difference in PUC exported from the subject country and the goods product produced by the Indian industry. The like article produced by the DI is comparable to the subject goods exported from subject country in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

10. Thus, the Authority proposes to hold that the goods produced by the applicant DI are like article to the PUC exported from the subject country, in accordance with the AD Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1 Views of the Domestic Industry

11. Following submissions have been made by the DI:

- i. The petition has been filed by M/s. Gujarat Credo Mineral Industries Limited & M/s. Chemical India. The petitioners are not related to any importer in India or exporter from subject country, nor have the petitioners imported the PUC within the meaning of Rule 2(b). The production of the petitioners constitutes total Indian production. The petitioners have, therefore, satisfied the requirement of standing and constitute DI within the meaning of the Antidumping Rules.
- ii. Petitioners are the only producers of the subject goods in the Indian market during relevant period. As per petitioner's market intelligence there are no other known producer of subject goods in the domestic market. Other producers namely, NALCO and Gujarat Multi Gas Base Chemicals Pvt. Ltd. who were known to produce earlier, were contacted by the petitioner. However, no information has been provided to the petitioner with regard to production by these companies. None of them have responded despite several attempts made by the petitioners and thus it was considered that the petitioners are the only domestic producers in the domestic market. The Authority may investigate and seek further information in this regard. Even if these alleged other producers still produce subject goods, the production by the petitioners would still remain a major proportion of total Indian production.

C.2 Views of Interested Parties

12. The following submission has been made in this regard –

- i. Applicants have falsely claimed to be the sole producers of the subject goods when they themselves have admitted to their being multiple other producers, such as NALCO and Gujarat Multi Gas Base Chemicals Pvt. Ltd. involved in production of the same.
- ii. Entire production of the Applicants cannot constitute a major proportion' of the total domestic production in India. Must include production of NALCO and Gujarat Multi Gas Base Chemicals Pvt. Ltd.

C.3 Examination by the Authority

13. The application was filed by M/s Gujarat Credo Mineral Industries Limited & M/s. Chemical India. The Authority notes that the applicants are not related to any importer in India or exporter from subject country, nor have they imported the PUC within the meaning of Rule 2(b).
14. As regards the claims that there are other Indian producers of the subject goods namely, NALCO and Gujarat Multi Gas Base Chemicals Pvt. Ltd., it is noted that evidences have been provided by the applicants showing repeated attempts made by them as regards possible production by other Indian producers, if any. However, none of other companies have come forward with regard to their possible production. Relevant information was also sought from concerned administrative authority. No evidence has been brought on record which shows production by any other producer of the subject goods. In view of the same, the Authority proposes to hold that the production of the applicants constitutes a major proportion in the Indian production.

15. It is, thus, determined that the applicants constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules and the application made by them is held as made on behalf of the DI. Further, the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules.

D. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

D.1. Views of the Domestic Industry

16. The following miscellaneous submissions have been made by the DI:
- i. The change in figures between the original NCV petition and the first updated petition in terms of profit & loss and cost of sales is only in the POI as a result of the extension of the POI by the Authority from March 2017 to July 2017. In the second updated information, the cost reflected for the year 2013-14 has been normated, in view of the recommencement of production by Chemicals India, to reflect a realistic condition of the DI. Difference in figures relating to market share is because at the time of filing of the petition secondary data was used while the updated information was filed with the DGCI&S T-by-T data.
 - ii. Transaction wise import data has been provided for the placement in the public file. DI has segregated detergent grade zeolite from other items coming under the HS Code 38249022 based upon the description provided in the transaction wise data and DI's knowledge about the importer of the PUC. The Authority may correlate this information with the importers name provided in the transaction wise DGCI&S data and the information furnished by the exporters.
 - iii. Arguments raised on non-disclosure of landed price, market share of petitioners, other producers, subject imports and non-subject imports are irrelevant as the same have already been provided. All relevant information has been provided in the petition and the updated information filed pursuant to change in POI. Adjustments claimed by the DI are according to the best available information to the DI and are in consonance with the practice followed by Authority. The petitioners relied upon DGCI&S data for filing of the updated petition as the POI was extended by the Authority.
 - iv. NALCO's ability to reduce cost of production by 20% by using Sodium Aluminate Liquor along with its state of the art production facility for producing Zeolite 4A is reflected in its inability to produce and sell the PUC. It is unheard of any business achieving such landmarks and then not producing to the extent of capacities created. The non-production of the invoices by users/consumers of the other Indian producers in itself evidences the non-production of PUC by the other Indian producers.
 - v. Change in original petition and subsequent updated information is because import data used at time of filing of the petition was procured from secondary source which was subsequently changed to DGCI&S transaction wise data. Also, the DGCI&S published data, which is being referred to, may not report all the imports coming under other codes apart from the dedicated code. DGCI&S transaction wise data shows that there has been a significant increase in imports in the POI.
 - vi. The DI has disclosed actual figures for volume parameters while the exporters have claimed complete confidentiality on their data including information of exports, sales production etc. but are demanding the same from the DI. Certain related/ group companies have even found it irrelevant to respond and participate in the investigations. The yardsticks of claiming confidentiality cannot be different for domestic producers and exporters.

D.2 Views of Interested Parties

17. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties in this regard –
- i. There are inconsistencies between the data provided in Original Petition, First Updated Information and the Second Updated Information in the profit-loss, cost of sales and market shares.
 - ii. Transaction-wise import data has not been made available. Products other than the PUC which falls under the HS Code 38249022 has been taken for the purpose of analysis. In light of the same the methodology used for sorting the import data should be provided.
 - iii. Unjustified Request for Confidential Treatment has been made by the petitioners; Landed price of the subject imports have to be disclosed in actual figures as it does not contain confidential information; they have also not provided the market share of the petitioners, other producers, subject imports, non-subject imports.
 - iv. Information regarding all economic parameters, imports, normal value, market share, dumping margin and soft

copy (Excel file) of T-B-T import data has not been provided for April 2016 to June 2017.

- v. NALCO's ability to reduce cost of production by 20% by using Sodium Aluminate Liquor along with its state of the art production facility for producing Zeolite 4A should have been considered by the Applicant while producing the PUC and NALCO should be included as an interested party in the present matter; Reference is laid on European Communities - Definitive Antidumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China, WT/DS397/AB/R.
- vi. Since, the volume and value of alleged dumped imports are based on data sourced from Seair Exim Solutions the same show a surge in imports. Applicant must submit DGCI&S data for proper evaluation of import data.
- vii. Applicant has provided data for 12 months only which is incomplete as per initiation notification; the initiation of present investigation cannot be said to be based on positive evidence for the POI and injury period considered in the initiation notification.
- viii. Import data of applicants is completely separate from Department of Commerce data.
- ix. Excessive confidentiality claimed with regard to performance of Applicants. The same has gone to the extent of concealing crucial data for determination of injury.

D.3 Examination by the Authority

18. Various interested parties have raised several issues with respect to the present investigation and the same are examined and addressed as under:
 - i. As regards the argument on the inconsistencies in the original petition and the first and second updated information, the Authority notes that POI proposed by the DI was extended and covered the period April, 2016-June, 2017 (15 Months). In view of this extended POI updated information of the industry was filed on the basis of DGCI&S published data whereas the petition was originally filed on the basis of secondary import data. The second updated information was filed by the domestic involving the import methodology and the injury information of the DI on the basis of normated costs in view of capacity installed by the one of the domestic producer. It is because of this reason that the figures are different. There is no inconsistency in the information filed by the DI.
 - ii. As regards the argument on transaction wise data not being made available and those products other than the PUC falling under the same code and yet taken for the purpose of injury analysis, the Authority notes that the transaction wise import data has been provided and placed in the public file. Detergent grade Zeolite has been segregated on the basis of the description as given in the transaction wise data. The data has been corroborated with the exporters' data as per its questionnaire response and has been found that as against *** MT volume of imports reported under DGCI&S data the import volume reported by the exporters in China are ***MT.
 - iii. As regards the argument of undue confidentiality claimed on various parameters by the interested parties, the Authority notes that confidentiality claim made by interested parties has been examined and found admissible as per the Rule 7 of the Antidumping Rules.
 - iv. As regards the claims raised on an alternate process as used by NALCO that should have also been considered by the DI, the Authority notes that concrete evidence has not been submitted in support of production of the subject goods by NALCO. In view of the same the Authority proposes to hold that NALCO is not engaged in the production of the subject goods and hence the claims on the alternate production process are not being considered.
 - v. As regards the claims that the data has been provided only for 12 months and thus initiation is not based on positive information for the POI considered for the present investigation, it is noted that Authority based on the positive information, prima facie, satisfied itself with fact of dumping causing injury to the DI. The POI has been extended by a quarter, thus major part of the POI was examined for the purpose of initiation. It was in order to make the POI close to the date of initiation that the POI was extended. It is also noted that the POI can be changed even during the course of the investigation as the purpose is to evaluate dumping causing injury to the DI in an appropriate period suitable for making objective assessment. In any case, the fact of dumping and injury is established in the present POI as can be seen from this Notification at relevant places.
 - vi. As regards the argument on the import data of the DI being different from that of the DGCI&S data, it is seen that that the because of non-availability of the DGCI&S Transaction wise data, the application was filed on the basis of the data obtained from secondary sources. This was later updated by the DI on the basis of transaction wise data obtained from DGCI&S. The Authority has also considered the updated data.

E. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

E.1. Views of the Domestic Industry

19. The DI *inter alia* submitted as follows:

- i. One of the provisions of Accession protocol has expired on 11th December, 2016. The Designated Authority should however proceed with present investigation considering Chinese producers as producers operating in non-market economy conditions due to reasons given below.
- ii. The investigation period considered by the Authority in the present case is April 2016 to June 2017 (15 months).
- iii. The purpose of fixation of POI is to consider a period when the existence of dumping causing injury is claimed and established. In the present case, a major part of the Period of Investigation falls before the expiry of the Chinese Accession Protocol and hence, it would be appropriate to consider China as a non-market economy.
- iv. The Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies for the reason that the costs and prices in China did not reasonably reflect the market forces during the POI. Para 8 to Annexure-I specifies the parameters which should be considered for grant of market economy status.
- v. Since Chinese companies were denied market economy status for the reasons mentioned in Para 8 of Annexure-I till December, 2016, petitioner submits that the Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies till such time the investigation period includes the period specified in Accession protocol.
- vi. Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
- vii. Normal value could not be determined on the basis of price of like article in an appropriate market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. The petitioner has claimed consideration of normal value on the basis of cost of production in India duly adjusted.
- viii. The dumping margin from China is not only significant, but also substantial, thus establishing existence of significant dumping of the PUC in India. The import volume of China has remained significant throughout the present injury period.
- ix. The adjustments claimed by the DI are according to the best available information to them and in consonance with the practice followed by the Authority. The exporters have filed responses and the Authority may after verification, and if found appropriate and correct may consider the actual adjustments.
- x. DI has provided normated figures for Gujarat Credo Minerals, on the basis of project report. The figures in the petition, do not reflect the real injury suffered by the DI, it is rather much lower injury suffered on basis of normated figures.

E.2 Views of Interested Parties

20. The following submissions have been made with regard to normal value, export price and dumping margin:

- i. The DI has claimed adjustments from Net Export Price but has not provided any evidence/ justification for the same.

- ii. Normal value determination in current investigation is flawed as the same should have been determined from the domestic sales and cost of subject goods in China PR, as provisions of para 15 (a)(ii) of Accession Protocol of China PR has been rescinded. The mandatory procedure prescribed by law in the present case has not been followed as the interested parties have not been put to notice about selection of the third country; no details, whether petitioners have made any adjustment on account of non-utilization of optimum capacity.
- iii. Normal value determined on the basis of the cost of production of the DI cannot be accepted as one of the petitioners is a newly incorporated entity, facing high cost of production.

E.3 Examination by the Authority

E.3.1 Examination of Market Economy Claims

21. At the stage of initiation, the petitioners proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination. The Authority sent copies of the questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard.
22. The Authority notes that none of the producers/ exporters of the subject goods from the subject country have submitted the 'Market Economy' questionnaire response on the facts & circumstances of the present case. In view of this non-cooperation, the Authority is unable to determine normal value in case of China PR on the basis of questionnaire response of the Chinese producers/ exporters.
23. None of the interested parties, including the DI, has made available any material to the Authority to determine normal value on the basis of costs or price in market economy third country. The Authority has, therefore, determined normal value in respect of China PR on the basis of best information available, in terms of rule 6(8) of the Rules.

E.3.2 Determination of Normal Value for Producers and Exporters in China PR

24. Normal value for the subject goods imported from China PR into India has been constructed considering best optimum consumption of the raw materials and utilities, and best estimates of conversion cost, interest, SGA, etc. including reasonable profit on the cost of production.

E.3.3 Determination of Export Price for China PR

25. The Authority notes that five exporters from China PR have furnished information to the Authority which could be used for determination of export price and individual dumping margin.
 - a. M/s. Inner Mongolia Risheng Recycling Resource Co., Ltd.
 - b. M/s. Tianjin Gerkwin International Trading Co., Ltd.
 - c. M/s. Chalco Shandong Advanced Material Co., Ltd
 - d. M/s. Chalco Qingdao International Trading Co.,Ltd.
 - e. M/s. Chalco Zibo International Trading Co., Ltd

26. Therefore, the Authority has analysed the response made by the exporters as follows:

M/s Inner Mongolia Risheng Recycling Resource Co., Ltd. (Producer) and M/s. Tianjin Gerkwin International Trading Co., Ltd., (Exporter) China PR

27. The Authority notes that Risheng has exported *** MT of the subject goods to India through trader Gerkwin International Trading Co. Ltd. They have claimed expenses on account of inland freight, ocean freight, marine

insurance, credit cost, bank charges, VAT and commission to Indian exporter. The same have been allowed, after due verification. Accordingly, the Authority has determined the ex-factory export price as *** US\$/MT.

M/s. Chalco Shandong Advanced Material Co., Ltd. (“Chalco AM”) (Producer), M/s. Chalco Qingdao International Trading Co.,Ltd. (Chalco Qingdao) (Exporter) and M/s. Chalco Zibo International Trading Co., Ltd (Chalco Zibo) (Exporter) China PR

28. The Authority notes that Chalco AM has exported *** MT of the subject goods to India through related trader Chalco Qingdao and *** MT of subject goods through another trader related trader, namely, Chalco Zibo. They have claimed expenses on account of Inland Freight, Ocean Freight, Marine insurance, credit cost, bank charges, and Commission to Indian exporter. The same have been allowed, after due verification. Accordingly, the Authority has determined the ex-factory export price as *** US\$/MT for Chalco AM for exports through their related trader Chalco Qingdao; and *** US\$/MT for their exports through the other related trader, namely, Chalco Zibo.

E.3.6 Normal Value & Export Price for non-cooperating producers/exporters

29. For all other producers/ exporters of China PR, export value has been determined based on facts available. Export price has been determined on the basis of DGCI&S transaction wise import data, after correlating the same with the questionnaire response filed by the responding exporters. The Authority notes that there is no major difference in the export price reported by the responding exporters and the export price determined on the basis of the DGCI&S data. Since these are CIF export price, these have been adjusted for expenses such as ocean freight, insurance, port expenses, bank charges, inland freight, commission and VAT to determine ex-factory export price.

E.3.7 Dumping Margin determination

30. The dumping margin for subject goods has been determined by comparing normal value and export price at ex-factory level for the subject goods. The table below shows the weighted average values for the responding exporters and subject country.

Table

| Producer | Exporter | Normal Value (USD/MT) | Net Export Price (USD/MT) | Dumping Margin (USD/MT) | Dumping Margin (%) | Dumping Margin (Range%) |
|---|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| M/s. Inner Mongolia Risheng Recycling Resource Co. Ltd (IMRRCL) | M/s. Tianjin Gerkwin International Trading Co. Ltd. (TGITCL) | *** | *** | *** | *** | 65-75% |
| M/s. Chalco Shandong Advance Material Co. Ltd.(CSAMCL) | Chalco Zibo International Trading Co. Ltd (CZITCL) | *** | *** | *** | *** | 85-95% |
| M/s. Chalco Shandong Advance Material Co. Ltd.(CSAMCL) | Chalco Qingdao International Trading Co. Ltd (CQITCL) | *** | *** | *** | *** | 80-90% |
| Others | Others | *** | *** | *** | *** | 100-110% |

31. It is seen that the dumping margins are more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules in respect of all imports into India.

F. INJURY AND CAUSAL LINK

F.1 Views of the Domestic industry

32. As regards injury and causal link, the DI has made submissions as under:
- i. Examination of material injury is not a mere trend analysis between base year and POI and any conclusion reached based on such an analysis can be misleading and will not be objective. Increase or decrease in trend is not the only yardstick to measure injury. Examination of the economic situation of the DI should take into account events within the injury period and that 2013-14 should be ignored for the purpose of injury analysis.
 - ii. The petitioner companies made sufficient and enough attempts at reaching out to other Indian producers. However, none of them responded despite several repeated attempts. The petitioners had also approached the concerned Administrative Ministry to provide information regarding the same. On the basis of market intelligence, the other producers are not engaged in the production of the subject goods.
 - iii. The cost and profits/losses of GCMIL have been considered as per normated capacity utilization as per project report. The data of GCMIL has not been considered at normated levels. The actual injury suffered by GCMIL is much higher than what has been taken for the purpose of analysis. Increased production and sale figures are because of the commencement of production by GCMIL. The price injury that is claimed is because of the dumped imports from the subject country.
 - iv. Despite an increase of 7% in market share of the DI, it still remains miniscule despite having sufficient capacity to cater to the entire domestic demand whereas market share of imports remain significantly high. Imports increased in absolute terms, with significant increase during POI. Imports in relation to production and sales remain about 1000%. The market share of imports in demand was 93% in POI.
 - v. Comparison of actual profitability from 2013-14 would not show the correct picture as one of the petitioner company had just recommenced production and that too at miniscule level. The Authority may consider profitability by considering overhead costs at normal production levels.
 - vi. The landed price of imports is below the level of cost of sales, selling price and non-injurious price of the DI. Price undercutting has also increased. Landed price of imports declined in the POI without corresponding decline in cost of sales. The import price which was just below US\$ 500/MT in the beginning of injury period, increased to a level above US\$ 500/MT towards middle of 2013-14, when Chemicals India increased its production and sale. However, thereafter, prices declined steeply to a level as low as US \$ 320/MT. Decline in import price by about US \$ 180/MT is very significant in the nature of this product. Costs on account of raw materials have increased over this period. Chinese producers reduced their prices by about 40%, the sole cause of which is commencement of production by GCMIL and significant increase in production by Chemicals India.
 - vii. The extent of price undercutting has increased in POI with the commencement of production by GCMIL; as seen from confidential data submitted with the Authority ROI decreased to abysmally poor levels in the POI. The profits and ROI have to be normatted appropriately for abysmally low production figures and then only a reasonable picture emerges.
 - viii. Any abnormal cost for GCMIL on account of startup has been normated for the purpose of injury analysis. Alleged claims listing out various parameters from the annual report of GCMIL, are thus redundant.
 - ix. Position of DI in the base year in comparison to the following years is not indicative of the situation of DI as only Chemicals India re-commenced production in the base year at a very minute level. Imports have had an adverse impact on the performance of the DI.
 - x. Increase in volume parameters such as sales, production and utilization is because Chemicals India had only miniscule level of production in the base year and GCMIL started commencement in the POI thus showing natural increase in these parameters.
 - xi. Production and sales is much below the optimum level despite DI having sufficient capacity to cater to domestic demand. Landed price of imports is significantly below the level of costs and selling price of DI causing adverse impact on the DI.
 - xii. One of the petitioner company recommenced production from the base year and was expecting to increase production and sales and profitability however dumped imports prevented it from doing so. The import price

- declined significantly when GCMIL started production in the POI. This caused significant adverse effect on the prices of the DI.
- xiii. Even with the normated cost, the DI shows significant losses in the POI. Blaming injury on start-up costs when stated repeatedly that normated costs have been taken for GCMIL is unwarranted. The exporters must answer the significant reduction in import prices.
 - xiv. All cost related parameters have been on a normated basis so that a fair and objective analysis takes place. The claimed injury is not due to abnormal increase in depreciation, wages or interest expenses.
 - xv. Price undercutting is the cause of injury and price underselling reflects the impact of dumped imports on the DI. Price undercutting led to significant adverse effect on profits, cash profits and ROI.
 - xvi. Significant level of price undercutting resulted into price suppression/depression effect on the domestic prices and has resultantly forced the DI to keep selling price much below the level of normated costs (and not actual costs) resulting into financial losses. Low priced imports at significant level captured significant portion of the legitimate share of the DI in the market. Imports have clearly caused injury to the DI.
 - xvii. The inventories too of DI have increased substantially over the injury period. In the post-POI period, the inventory has increased to almost 600 MT.
 - xviii. The production and sales of DI in the base year was close to zero, and hence any increase thereafter would show a massive jump in the production and sales of the DI in indexed terms.
 - xix. Information as submitted after normating the costs shows that cost of sales have increased throughout the injury period whereas selling price has declined. Landed price of imports has declined sharply in the POI and is below the level of costs and selling price of DI. Imports are having significant depressing effect on the prices of the DI. Price underselling is not a parameter laid down under law indicating injury.
 - xx. The imports constitute 93% of the demand and there is no evidence of production of the subject goods by any other producers other than the DI.
 - xxi. The NIP for GCMIL can be determined at the level of normated production. The DI fails to understand the logic behind optimized cost for price undercutting analysis as it involves the difference between landed price of imports and selling price. In any case the cost of sales provided by the DI is normated.

F.2 Views of Other Interested Parties

33. Submissions made by the other interested parties are as under:

- i. Sales of other domestic producers which are useful for calculating the market share and assessing the injury suffered by the Petitioners on account of the other domestic producers is absent.
- ii. DI has claimed material injury for both the companies in the present investigation in order to camouflage the start-up costs and losses suffered by GCMIL; the fact that GCMIL has recently started production has been selectively used as per the convenience of the petitioners, however, while assessing price injury, the Petitioners have strategically not dealt with the issues with respect to increased costs and initial losses suffered by GCMIL.
- iii. The market share of the Petitioners has increased to 7% in the POI as compared to the base year.
- iv. The profitability of the Petitioners has been declining rapidly from 2014-15. The profitability when compared to the base year, declined by 69 index points in 2014-15, while landed price actually increased by 1 index point during the same period.
- v. If price undercutting did affect the Petitioners, there should have been a drastic decline in the return of investments in the POI when compared to the base year which was not the case in the present factual matrix. [ROI is in the same range for the entire injury period]
- vi. GCMIL's commencement of production since the POI has led to the Petitioners showing injury. This injury is due to the high costs and losses that are reflected in financial indicators such as financial costs, short term borrowing, and trade payables.
- vii. DI has provided selective injury information and with a significant variance for many injury parameters in latest file as compared to original file, due to which, respondents cannot provide any meaningful comments.
- viii. DI has not suffered injury in following parameters – capacity utilization, production and capacity have significantly increased during injury period; domestic sales and market share witnessed a massive rise and reflects no injury to industry; wages and no. of employees have been held confidential, since production has increased these parameters also have increased; productivity information is confidential, since production has increased this must have also improved; the correct way to analyze the inventories is to compare the closing inventories with the domestic sales

made by the DI as laid down by the Hon'ble CESTAT in the case of *Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) Vs. DA 2011 (270) E.L.T. 696 (Tri. - Del.)*; No adverse impact on the Growth of the DI.

- ix. No price injury as DI began producing during injury period and thus, will make lower price for product only; same has not been impacted by imports. Also market share of subject country imports declined in injury period
- x. Increase in cost of depreciation, wages and interest has been due to purchase of new machinery from high investment not due to subject country imports; the impact of increase in capacity on the cost of the DI is also required to be analyzed when there is an increase in capacity as laid down by the WTO Panel in China-Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from US.
- xi. Increase in imports is not a factor of injury as sales of the DI have increased over the injury period; no conclusion of injury can be drawn on the basis of price undercutting and price underselling as both are not factors of injury.
- xii. The inventories of DI have declined; increase in production, sales and market share is unprecedented.
- xiii. No evidence of price effect by imports and there was no evidence that DI is experiencing injury hence, no causal link. Injury due to increase in costs and enhancement of capacity and *inter-se* competition.
- xiv. DI has failed to provide data substantiating the claim of injury and economic parameters such as net sales realization, actual and potential negative effects on cash flow, wages, growth, ability to raise capital investments.
- xv. Sales and production of the subject goods by DI have increased at a rate which is higher than increase in demand whereas the imports have not increased as much in comparison.
- xvi. There is no price suppression/depression as cost of sales declined and there is no claim for price underselling
- xvii. DI facing inter-se competition in terms of price of the subject goods and the same is evident from lack of participation of other producers.
- xviii. NIP could be determined by considering data from other producers than M/s Gujarat Credo Mineral Industries Ltd. Alternative analysis of the same should be done. Cost of production being high on account of start-up cost, the Authority is requested to adjust the cost of production and NIP so as to arrive at fair determination of price undercutting.

F.3 Examination by the Authority

34. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and also the DI. The Authority has examined the injury to the DI in accordance with the Antidumping Rules and considering the submissions made by the other interested parties appropriately.
35. The injury analysis by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties. This includes correction of a minor calculation error, as was pointed out in the comments on the Disclosure Statement issued earlier.
36. For the examination of the impact of the imports on the DI in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules *supra*.
37. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the DI before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

F.3.1 Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

(a) Demand and Market Share

38. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

| Particulars | Units | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | POI-A |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------|
| Demand | | | | | |
| Sales of DI | MT | *** | *** | *** | *** |
| Sales of Other Indian Producers | MT | - | - | - | - |
| Imports from Subject Countries | MT | 24,929 | 25,927 | 31,022 | 31,809 |
| Imports from Other Countries | MT | 54 | 77 | 53 | 75 |
| Total Demand/Consumption | MT | *** | *** | *** | *** |
| Market Share in Demand | | | | | |
| Sales of DI | % | 0% | 1% | 4% | 7% |
| Sales of Other Indian Producers | % | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Imports from Subject Countries | % | 100% | 99% | 96% | 93% |
| Imports from Other Countries | % | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Total Demand/Consumption | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

39. The Authority notes that the demand for the PUC has increased throughout the injury period. Major share of market is being held by imports from subject country. The share of the DI in the demand is in minority, despite sufficient capacities with the DI, due to dumping in the Country.

(b) Import Volumes and Share of Subject Country

40. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject country has been analyzed as under:

| Particulars | Units | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | POI-A |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Volumes | | | | | |
| Subject Country | MT | 24,929 | 25,927 | 31,022 | 31,809 |
| Other Countries | MT | 54 | 77 | 53 | 75 |
| Total Imports | MT | 24,983 | 26,004 | 31,076 | 31,884 |
| Market Share in Imports | | | | | |
| Subject Country | % | 99.78 | 99.70 | 99.83 | 99.77 |
| Other Countries | % | 0.22 | 0.3 | 0.17 | 0.23 |
| Total Imports | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Subject Country Import in Relation to Indian Production | % | 830970 | 9804 | 2320 | 1336 |
| Subject Country Import in Relation to Consumption | % | 100 | 99 | 96 | 93 |
| Subject Country Import in Relation to Total Imports | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

41. It is noted that the import volume from subject country has increased throughout the injury period in absolute terms and have registered significant increase in the POI. Imports from other countries are negligible throughout the injury period.

42. Imports in relation to Indian production and consumption have declined in view of the commencement of production by GCMIL in the POI and recommencement of production by Chemicals India.

F.3.2 Price Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

43. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred, in normal course. The impact on the prices of the DI on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression

and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the DI have been compared with the landed price of imports from subject country.

(c) **Decline in Import Price**

44. One of the petitioners commenced commercial production w.e.f. June 2016 whereas the other producer had negligible production till 2013-14, while low production in 2014-15. It is seen from the import price of the product over the injury period that the import price started declining in 2015-16, with steep decline in the POI. The decline in the price in US\$ was steeper. Petitioners contended that the only reason for this steep decline in the import price was the commencement of production in India.

| Particulars | UOM | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | POI-A |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|
| Landed Price of Imports | Rs./kg | 32.65 | 33.03 | 31.18 | 24.52 |
| | Index | 100 | 101 | 96 | 75 |
| | US\$ | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.36 |
| | Index | 100 | 101 | 96 | 75 |

(d) **Price Undercutting**

45. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the DI in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the DI as below. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the DI net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the DI were determined at the ex-factory level.

| Particulars | Unit | POI-A |
|-------------------------|--------|--------|
| Landed Price of Imports | Rs./MT | 24,522 |
| Net Selling Price | Rs./MT | *** |
| Price Undercutting | Rs./MT | *** |
| Price Undercutting | % | *** |
| Price Undercutting | Range | 10-20% |

46. It is seen that the landed price has been below the net selling price of the DI. Thus imports are undercutting the prices of the DI

(e) **Price Underselling**

47. The Authority has also examined price underselling suffered by the DI on account of dumped imports from subject country. The same can be seen below:

| Particular | China | |
|------------------------------|--------|---------|
| | Rs/MT | US\$/MT |
| Non Injurious Price (NIP) | *** | *** |
| Landed Price | 24,522 | 363.56 |
| Price Underselling | *** | *** |
| Price Underselling (%) | *** | *** |
| Price Underselling (Range %) | 40-50% | |

48. It is seen that the DI has suffered significant price underselling on account of imports of the subject goods from the subject country.

(f) **Price Suppression and Depression Effects of the Dumped Imports**

49. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise

would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. In view of the fact that GCMIL came into existence in the POI and thus the actual cost will not be representative, the Authority has normated the cost based on the capacity utilization projected by the said producer as observed from the Project Report. The position is shown as per the table below:

| Particulars | UOM | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | POI-A |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|
| Cost Of Sales | Rs./kg | *** | *** | *** | *** |
| <i>Index</i> | | 100 | 103 | 106 | 108 |
| Selling Price | Rs./kg | *** | *** | *** | *** |
| <i>Index</i> | | 100 | 97 | 99 | 93 |
| Landed Price of Imports | Rs./kg | *** | *** | *** | *** |
| <i>Index</i> | | 100 | 101 | 96 | 75 |

50. It is seen that the cost of sales has increased over the injury period whereas the selling price of the DI has declined. The selling price is below the level of cost of sales. It is further noted that landed price of imports have declined steeply in the POI and are much below the level of selling price and costs of production of the DI. Further, whereas the cost of production of the DI increased, its selling price declined. The imports are causing significant price depression and suppression in the domestic market.

F.3.3 Examination of Economic Parameters Relating to Domestic Industry

51. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the DI should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
52. Accordingly, various economic parameters of the DI are analyzed herein below:

(a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

53. The performance of the DI with regard to production, capacity, capacity utilization and sales are as follows:

| Particulars | UOM | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | POI-A |
|----------------------|-----|---------|---------|---------|-------|
| Capacity | MT | *** | *** | *** | *** |
| Production | MT | *** | *** | *** | *** |
| Capacity Utilization | % | *** | *** | *** | *** |
| Sales | MT | *** | *** | *** | *** |

54. The capacity with the DI increased in the POI with the commencement of production by one of the domestic producer, i.e., GCMIL. Production and sales have shown some increase over the injury period as a consequence of commencement of production by one of the DI and recommencement of production by other domestic producer. Chemicals India provided information with regard to its production since 2013-14 and submitted that the company has restricted its production due to Chinese dumping. The company had earlier been producing and selling in the domestic market. However, they reduced their production significantly, with reduction in the prices of the Chinese producers during 2007-08. Thereafter, as the price increased once again in 2013-14, the company recommenced its production. However, production level of both the domestic producers are still at fairly low levels. Despite sufficient demand and establishment of capacity by the new producer, the DI is not operating at its optimum

level.

(b) Market Share in Demand

55. The effects of the dumped imports on the market share of the DI have been examined as below.

| Particulars | Units | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | POI-A |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|
| Market Share in demand | | | | | |
| Sales of DI | % | 0% | 1% | 4% | 7% |
| Sales of Other Indian Producers | % | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Imports from Subject Country | % | 100% | 99% | 96% | 93% |
| Imports from Other Country | % | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Total Demand/Consumption | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

56. It is noted that the market share of the DI has marginally increased while that of the subject country has marginally declined. This is in view of the fact that M/s Chemicals India recommenced the production in 2014-15 and GCMIL started production in the POI. It is seen that share of the DI in the market is just 7% as against the share of the imports which constitutes 93% in the POI despite having an installed capacity that could supply up to 55% of the domestic demand.

(c) Inventories

57. It is seen that the average inventory levels of the DI have increased over the injury investigation period. However, the inventory levels with the DI were still quite low considering the demand in India and sales of the DI. The DI also submitted that the inventory levels with the DI increased very significantly in the post-POI period and the inventory levels with the DI were low only because restriction on production.

| Particulars | UOM | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | POI-A |
|-------------|-----|---------|---------|---------|-------|
| Opening | MT | - | *** | *** | *** |
| Closing | MT | - | *** | *** | *** |
| Average | MT | - | *** | *** | *** |

(d) Profits, Return on Investment and Cash Flow

58. Performance of the DI with regard to profit, return on investment and cash flow is as follows:

| Particulars | UOM | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | POI-A |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Profit/(Loss) | Rs./Kg | *** | *** | *** | (***) |
| <i>Trend</i> | | 100 | 31 | 19 | (69) |
| Profit/(Loss) | Rs.Lacs | *** | *** | *** | (***) |
| <i>Trend</i> | | 100 | 2687.5 | 9225 | (53962) |
| Cash Profit | Rs.Lacs | *** | *** | *** | *** |
| <i>Trend</i> | | 100 | 2411 | 8833 | 237466 |
| Return on Capital Employed | % | *** | *** | *** | *** |
| <i>Trend</i> | | 100 | 2350 | 4867 | 8.33 |

59. In view of the fact that GCMIL came into existence in the POI and thus the actual cost will not be representative, the Authority has normated the cost based on the capacity utilization projected by the said producer as observed from the Project Report.

60. It is seen that profitability of the DI has declined and the DI is incurring substantial losses in the POI. The cash flow has improved over the injury period. The return on capital employed was low and remains barely positive in the POI. Return on capital employed declined in the POI once again after improving in 2015-16.

(e) Productivity

61. It is seen that productivity in terms of productivity per day as well as per employee, has increased over the injury period, which is in line with the movement of production. However, despite this improvement in productivity, profitability declined.

| Productivity | UOM | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | POI-A |
|--------------|-----|---------|---------|---------|-------|
| Per Employee | Nos | *** | *** | *** | *** |
| Per Day | Nos | *** | *** | *** | *** |

(f) Employment and Wages

62. It is seen that the employment with the DI and the wages paid have increased over the injury investigation period.

| Particulars | UOM | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | POI |
|-------------|----------|---------|---------|---------|-----|
| Employment | Nos | *** | *** | *** | *** |
| Wages | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |

(g) Growth

63. The growth of the DI in terms of volume parameters has been positive in view of commencement of production by GCMIL, while growth in terms of price parameters is negative. However, even in respect of volume parameters, the growth was far below what could have been the growth, given the capacities created in India, demand for the product and capacity utilization achieved by the DI in the past.

| Growth | UOM | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | POI-A |
|-------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| Production | % | - | 8,715 | 406 | 78 |
| Capacity Utilization | % | - | 4 | 15 | (5) |
| Domestic Sales Quantity | % | - | 8,698 | 407 | 76 |
| Selling price per unit | % | - | -3.02 | 2.23 | -6.23 |
| PBT per unit | % | - | -69.17 | -32.45 | -432.62 |
| ROCE | % | - | 2268 | 107 | -100 |

(h) Ability to Raise Capital Investment

64. The Authority observes that the DI recently made investments, which are performing very adversely.

(i) Level of Dumping & Dumping Margin

65. It is seen that imports from the subject country are entering at dumped prices and that the margin of dumping is significant.

(j) Factors Affecting Domestic Prices

66. The examination indicates that there is a healthy demand in India for the subject goods. The landed value of subject goods from subject country is below non injurious price, cost of sales and selling price of the DI. It is also observed that imports from other countries are almost non-existent. Thus, factor affecting the domestic prices are primarily the import prices.

(k) Magnitude of Injury and Injury Margin

67. The non-injurious price of the subject goods produced by the DI as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the imports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

Injury Margin Table

| Particular | M/s Inner Mongolia Risheng Recycling RCL | | Chalco Zibo International Trading Co. Ltd | | Chalco Qingdao International Trading Co. Ltd | | All Other Producers/ Exporters | |
|------------------------------|--|--------|---|--------|--|--------|-----------------------------------|--------|
| | Rs/MT | US\$ | Rs/MT | US\$ | Rs/MT | US\$ | Rs/MT | US\$ |
| Non Injurious Price (NIP) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Landed Price | 24,582.83 | 364.46 | 24,471.66 | 362.81 | 24,360.73 | 364.52 | 21,631.05 | 320.70 |
| Injury Margin | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Injury Margin (%) | *** | | *** | | *** | | *** | |
| Injury Margin (Range%) | 40-50% | | 40-50% | | 40-50% | | 60-70% | |

(I) Other Known Factors & Causal Link

68. Having examined the existence of continued injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the DI, in terms of its price undercutting and price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Antidumping have been examined by the Authority herein below to see whether any factor, other than the dumped imports, could have contributed to the injury suffered by the DI.

i) Volume and Prices of Imports from Third Countries

69. It is seen that imports from other countries are almost non-existent and, hence are not causing injury to the DI.

ii) Contraction of Demand

70. There has been an increase in demand throughout the injury investigation period and thus the same cannot cause any injury to the DI.

iii) Changes in the Pattern of Consumption

71. The pattern of consumption with regard to the PUC has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the DI.

iv) Developments in Technology

72. Technology for production of the product concerned has also not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

v) Conditions of Competition and Trade Restrictive Practices

73. There is no trade restrictive practice in place.

vi) Export Performance of the Domestic Industry

74. The performance of the DI and injury thereto has been examined with respect to the domestic performance to the extent possible. No export sales were made by the DI throughout the injury investigation period and so the same is not a possible cause of injury to the DI.

vii) Performance of Other Products Produced and Sold by Domestic Industry

75. The performance of other products being produced and sold by the DI has not affected the assessment made by the Authority of the DI's performance. The information considered by the Authority is with respect to the PUC only.

viii) Productivity of the Domestic Industry

76. The Authority notes that the productivity of the DI has followed the same trend as production and shows increase.

Deterioration in productivity is not a cause of injury to the DI.

G. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

77. The Authority has noted the concerns expressed by the user industry and importers. Given that the purpose of Antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the DI by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country, the Authority feels that creation of a balanced and equitable environment for both the manufactures; exporters; importers and users is in all-round interest.

H. POST DISCLOSURE COMMENTS

H.1 Views of the Domestic Industry

78. Post disclosure submissions made by the DI are as follows:

- i. Chemicals India is not a new producer and commenced production in 1992. Unfairly priced imports led to the company ultimately stopping production in 2008-09. Upon normalization of prices it resumed production however, as it increased production the import volumes from the subject country increased at lowered prices despite the increase in costs.
- ii. GCMIL is a joint venture between a state owned PSU and a public limited enterprise set up for the purpose of mineral development in the state. The plant was set up in an underdeveloped area to boost socio-economic development in the region. Production began in 2016 but it leads to lowered prices of the subject imports thereby forcing it to lower its prices in the year of commencement only
- iii. In the absence of any MET Questionnaires to determine normal value, it has been rightly noted that China cannot be given market economy treatment. Because of failure to disclose vital information, such as name of their related parties, details of their related party producing product under consideration, suppression of facts regarding benefits & incentives received by them, the responses should be rejected. The related parties of the exporters involved in the production and sale of subject goods have also not participated.
- iv. Awarding two dumping margin/injury margin ranges in the name of two different channels gives an undue, unintended leverage to the producer to attract a duty lower. Anti-dumping duty for the common producer should collapse and there should be one unique duty for every producer and one unique duty for every exporter.
- v. Despite the increase in demand throughout the injury investigation period, the majority share of the market is held by the subject imports even when the DI has sufficient capacity.
- vi. Import volumes have increased in absolute terms while in relation to production and consumption have declined because of commencement of production by GCMIL and recommencement of business by Chemicals India yet remain significant in relative terms as well, 1336% of Indian Production and 93% of Indian consumption.
- vii. Landed price has declined since 2014-15 and showed a significant decline in the POI. Declining prices are a result of commencement of business by GCMIL and recommencement by Chemicals India. The cost of raw materials increased during this period. Normated Data as considered by the Authority also shows injury.
- viii. GCMIL Plant was operational in POI which shows addition of capacity resultantly showing increased production and sales. Despite increased production and sales, production for the DI is at fairly low levels.
- ix. Even when the optimum production is considered there would have been immense inventories accumulated and the optimum production should not be considered only for NIP purposes but for all other purposes as well. The inventories have further increased in the post POI period.
- x. Even with the normated costs there has been significant decline in profitability and DI is suffering from substantial losses and barely positive ROCE.
- xi. Fixed form of anti dumping duty is required to be imposed for a period of five years expressed in US/MT.

H.2 Views of the other Interested Parties

79. Post disclosure submissions made by other interested parties are as follows:

- i. The Authority has disclosed the landed prices of the goods exported by Chalco and the other responding parties but has not disclosed the aggregate NIP of the DI and the non-confidential version of various economic parameters

- such as inventory, wages, productivity, capacity, production, sales, capacity utilization neither in indexed nor in percentage terms. The Authority is requested to disclose the all economic parameters of DI in indexed terms such that it does not hamper the ability of the respondents to make meaningful comments.
- ii. The landed value and the subsequent injury margin for the non-participating producers should be done on the basis of the DGCI&S data, however, the Authority has considered responding exporter's price.
 - iii. It has been wrongly determined that the petitioners are the only producers of the subject goods in the country. As per information obtained from the RTI Act and from its corporate presentations, it is shown that NALCO is engaged in the production of detergent grade Zeolite. Since the Authority has the power to seek information from other ministries, the same may also be done for seeking necessary information from the Ministry of Mines.
 - iv. NALCO has certain advantages over other Indian producers such as raw material advantage, same facility for alumina and zeolite 4A production, state of the art production facility which is resulting in lower cost of production by NALCO as compared to the petitioners. It should be examined if the injury to the petitioners is because of obsolete process and competition with NALCO.
 - v. The Authority has not used the methodology for determination of normal value as laid out in *Shenyang Mastushita S. Battery Co. Ltd. vs. Exide Industries Ltd.* The practice of the Authority of considering the normal value on the basis of the DI's cost of production is inconsistent with the practice followed by other WTO Members.
 - vi. Since GCMIL only commenced production in the POI, it can only claim material retardation and not material injury. And since it is a new producer, the Authority should determine the NIP only after exclusion of data of GCMIL. The financial costs and other such costs have only increased because of commencement of production. Reference in this regard is laid on the FF issued in the case of SBR wherein the determination of the NIP was on the basis of the data of the established producer alone.
 - vii. The Authority has evaluated the economic parameters of the DI in a contradictory manner as at one place it has been noted that Chemicals India commenced production in 2014-15 and that GCMIL commenced production in the POI while at another place it has been noted that Chemicals India provided information on production since 2013-14. The base year in the investigation period cannot be excluded on the grounds of low production volumes.
 - viii. The price undercutting has been examined by the Authority for the POI but as per the practice of the Authority it has to be examined for the entire injury investigation period. As regards the claims of the DI regarding an increase in cost in the POI, the price of inputs soda ash and bauxite does not reflect this claimed price rise.
 - ix. Widening of scope of PUC by including various codes within chapter 38 and 28 has been sought for without providing any sufficient evidence.
 - x. Petitioners had submitted in their written submissions that product under consideration falls under Chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975. The subject goods were classified under customs sub-heading 38249022 at the time of filing of petition; but the classification has thereupon changed to 38249922. Further transaction wise segregation of imports shows that subject goods are being imported under various codes. The investigation is product under consideration specific and not HS Code specific. HS Codes are only indicative and not binding on the scope of PUC.
 - xi. The Authority is requested to clarify what factors have been considered while normating the costs of DI and disclose the calculation on a non-confidential basis.
 - xii. The normal value and export prices be calculated on the basis of the information filed by the cooperating exporters and producers. The Authority is requested to disclose the ranges/indexed figures considered for cost of production, SGA etc.
 - xiii. The analysis of market shares or the capacity utilization otherwise than the increase or decrease in these factors is not mandated to be carried out as per Annexure II. Both the market share and capacity utilization have significantly improved over the injury period. Analysis of sufficient utilization of capacity is not relevant and so no injury can be recorded for these parameters. Since production, sales and market share have increased significantly from the base year till the POI no injury can be recorded on these factors.
 - xiv. Price undercutting and price underselling are not the factors of injury as has been laid down by the Hon'ble CESTAT in the case of *Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) Vs. DA 2011 (270) E.L.T. 696 (Tri. - Del.)*.
 - xv. No reasons or analysis has been recorded for the increase in the cost of the DI. It only increased because of their inefficiency and losses. There is no analysis as to how the performance of the DI improved despite of subject imports.
 - xvi. Analysis of inventory on basis of average inventory is incorrect as it ought to be made on basis of closing inventory as percentage of sales/production. It will indicate that the inventories of the DI have significantly come down over the injury period

- xvii. There is a significant difference between the dumping margin for Risheng Gerkwin group and other exporters. There ought to be a significant difference in the injury margin for the same as prices of Risheng Gerkwin group are higher than the prices of other exporters. It is requested that the same may be rechecked.

H.3 Examination by the Authority

80. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties are being examined as below:
- i. As regards disclosure of data, the Authority notes that confidential information cannot be disclosed in the public document. The Authority has already disclosed non confidential version of the information, to the extent feasible in the Disclosure Statement, issued earlier, and in the present findings. Further, the Authority has already given a detailed analysis which also enabled the interested parties to understand the substance of information provided on confidential basis and so adopted by the Authority.
 - ii. As regards margins for the non-responding exporters, the same have been determined as per Rule 6(8) and past practise of the Authority. In case of non-cooperating exporter, the Authority can consider import price after evaluation of DGCI&S import data and questionnaire response of the exporter. In fact, it is found that the DGCI&S data in fact shows imports at even lower price.
 - iii. As regards production by NALCO, the Authority reiterates that the investigation has shown that NALCO has not produced the product during the POI. The Company has confirmed to the Authority that production of Zeolite-4A from by NALCO had been stopped from first week of Dec-2013. The company has claimed that its production was stopped mainly due to low marketability as the mineral Zeolite supplied from other countries were much cheaper than theirs. While the reason cited by the company was not separately verified by the Authority, nonetheless, NALCO has not produced the PUC during the period of investigation of this case.
 - iv. As regards consideration of appropriate market economy third country, the Authority notes that none of the interested parties suggested any market economy third country which could be considered for determination of normal value. While the petitioner contended that no public information was available in this regard, the interested parties also did not provide any useful information. The Authority is therefore constrained to resort to “any other reasonable basis”, i.e., construction of normal value as permitted under law.
 - v. As regards the contention concerning inclusion of GCMIL for the purpose of injury and injury margin determination, the Authority notes that the present decision is consistent with the past determinations on this account. GCMIL has commercially started producing and selling the subject goods in the POI from the month of July 2016 and was commercially in operation for 12 months of the POI out of 15 months (April 2016-June 2017). In the SBR Case, Reliance had declared commercial production only in the post POI. As regards possible higher cost of the company, the NIP has been determined considering the normated cost on account of commencement of production by GCMIL.
 - vi. It is clarified that Chemicals India had negligible production in 2013-14 and low production in 2014-15. The base year has not been excluded for injury examination. However, the costs have been appropriately normated for Chemicals India on account of low production in the base year and the cost of GCMIL has been normated for the POI on account of commencement of production by the company.
 - vii. As regards determination of price undercutting for the injury period, the Authority notes that the law requires analysing the price undercutting in the POI. The law does not require determination of price undercutting over the entirety of the injury period. While the increase in imports and price depression/suppression is required to be determined over the injury period, dumping margin, price undercutting and injury margin are determined only for the POI.
 - viii. As regards inclusion of Customs classifications, it is clarified that petitioners had submitted in their written submissions that product under consideration falls under Chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975. The subject goods were classified under customs sub-heading 38249022 at the time of filing of petition; but the classification has thereupon changed to 38249922. Further transaction wise segregation of imports shows that subject goods are being imported under various codes. The investigation is product under consideration specific and not HS Code specific. HS Codes are only indicative and not binding on the scope of PUC. It is also noted that one of the purpose of the investigations is to identify the article liable for ADD and the customs classification of the same.
 - ix. It is clarified that given the fact that one of the petitioner company commenced production in the POI while the

other recommended production in the base year of the injury investigation period and to examine the effects of the dumped products on the DI the costs of the DI have been appropriately normated. Being a new company and because of absence of any data of the previous years, the costs for GCMIL have been taken on the projection basis considered before commencement of the project wherein an optimal target of 70% utilization of the capacity was set considering the demand of the product in the country.

- x. As regards the contentions of the other interested parties that project reports are only assumptions and do not reflect a true picture, the Authority considers that whereas costs and investments of such magnitude are involved in a business, the company proceeds after due market research and intelligence, and after ascertaining viability of the product on the basis of feasibility and viability studies. Such feasibility and viability studies cannot be brushed aside. In any case, it has not been established that the such feasibility and viability studies are unrealistic in the present case.
- xi. As regards normation of costs for Chemicals India, it is clarified that the costs have been normated considering the utilization levels achieved in 2015-16 and considering the same to be optimum levels.
- xii. As regards increase in costs of the DI, it is noted that the raw materials costs have increased in this period and there is no evidence of inefficiencies on the part of the DI.
- xiii. Analysis of inventories by considering separately closing and opening inventories shows that the closing inventories are in fact higher than opening inventories.
- xiv. The dumping margin and injury margin for the responding exporters have been rechecked for the alleged difference in the same in terms of range of these. The same have been correctly reflected in these findings.

I. RECOMMENDATION

81. The Authority, considering the aforesaid notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the DI caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of Antidumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends anti-dumping duty on imports of subject goods from subject countries in the form and manner described hereunder.
82. With regard to duty structure, keeping into account the factual matrix of the case and having regard to contentions raised, information provided and submissions made by interested parties, it is deemed appropriate to recommend fixed form of anti-dumping duty denominated in US\$. Further, having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of Antidumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury for a period of five (5) years, so as to address the injury to the DI. Accordingly, Antidumping duty equal to the amount indicated in Col 7. of the table below is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from China PR:

Duty Table

| S.N. | Heading/ Subheading* | Description of Goods | Country of Origin or Export | Producer | Exporter | Duty Amount (USD/MT) |
|------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 38249922 38249090 38249990 28429090 28269000 28399090 28421000 | Zeolite 4A (Detergent Grade) | China PR | Inner Mongolia Risheng Recycling Resource Co. Ltd (IMRRRCL) | Tianjin Gerkwin International Trading Co. Ltd. (TGITCL) | 163.96 |
| 2 | -do- | -do- | China PR | Chalco Shandong Advance | Chalco Zibo International Trading Co. | 165.61 |

| | | | | | | |
|---|------|------|----------|--|---|--------|
| | | | | Material Co. Ltd. (CSAMCL) | Ltd (CZITCL); | |
| 3 | -do- | -do- | China PR | Chalco Shandong Advance Material Co. Ltd. (CSAMCL) | Chalco Qingdao International Trading Co. Ltd (CQITCL) | 163.90 |
| 4 | -do- | -do- | China PR | Any other than serial No. 1 to 3 above. | | 207.72 |

* Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC. The PUC mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code.

83. The duty rates as recommended above are applicable for exports by specified producer and exporter mentioned therein. The Customs should verify the name of the producer at the time of clearance of subject goods. Request for change in the name of a notified exporter will be considered by the Authority in accordance with the procedure laid down in Trade Notice No. 12/ 2018 dated 17th September 2018.
84. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
85. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General